16.38 hrs.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take discussion and voting on Demands No. 63 to 65 and 124 and 125 relating to the Ministry of Irrigation and Power for which 6 hours have been allotted.

28 cut motion have been tabled to these Demands.

Hon. Members desirous of moving cut motions may hand over at the Table within 15 minutes and numbers of the selected cut motions.

Hon. Members are already aware of the time-limit for speeches.

DEMAND NO. 63—MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 22,33,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Ministry of Irrigation and Power'."

DEMAND NO. 64—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 2,05,08,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Multi-purpose River Schemes'."

DEMAND NO. 65—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS AND OTHER EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 1,69,52,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Miscellaneous Departments and Other Expenditure under the Ministry of Irrigation and Power'."

DEMAND NO. 124—CAPITAL OUTLAY ON MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 2,47,69,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes'."

DEMAND NO. 125—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 2,97,07,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1961, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power'."

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब डिप्टी-स्पीकर साहब, इस मिनिस्ट्री ने अब तक जो काम किये हैं और अगले साल के लिये जो उन के प्रोग्राम हैं,मैं उन का समर्थन करता हूं । लेकिन साथ साथ मैं इस मिनिस्ट्री की वर्किंग की तरफ भी कुछ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । पिछले कई सालों से इस हाउस में इस डिमांड को दोहराया गया है कि जो माइनर इरिगेशन प्राजेक्टस हैं वह भी इरिगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री में शामिल करने चाहियें। यह इस लिय कि जहां तक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्टस का ताल्लुक है वह इस वक्त मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड एग्रिकल्चर के मातहत आती हैं,। लेकिन उन पर जितना कम काम होता है, और जितना समय उन पर लगता है, उस की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें होती हैं इस का अन्दाजा आप कर सकते हैं । हर साल इस हाउस में इस बात को दोहराया जाता है कि चूंकि मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर के पास न तो टेकनिकल नो हाऊ है और न वह इन प्रोजेक्ट्स को ठीक से एग्जामिन कर सकती है, न उन पर काम कर सकती है, इस लिये यह माइनर प्रोजक्ट्स जो हैं वह मिनिस्ट्री आफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट के पास चली जायें, और जो उन से बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम ५०,००० रु० से ऊपर की, वह मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन ऐंड पावर के पास चली जायें । अगर ऐसा किया जायेगा तो चाहे वह स्टेट्स के मातहत हों, चाहे उन का सुपरविजन सेन्टर के पास हो, उन का जो लैप्स रेशियो है वह बहुत कम हो जायेगा । आज उन का लैप्स रेशियो १५ परसेंट से ले कर ६५ परसेन्ट तक है । अगर १०० कामों में से ६५ काम कहीं पर न हों, तो आप जान सकते हैं कि लोगों पर उस का क्या असर हो सकता है । इसलिये सब से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जो माइनर इरिगेशन प्रोजक्ट्स हैं अगर वह ५०,००० रु० से ऊपर की हों तो उन को इस मिनिस्ट्री के नीचे रहना चाहिये ताकि उन पर ठीक से काम हो सके । अगर १० लाख रु० की भी प्रोजक्ट हो तो भी वह इरिगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री के अन्डर होनी चाहियें क्योंकि १० लाख रु० की स्कीम बहुत बड़ी स्कीम होती है । उस के जरिये कई हजार एकड़ जमीन का पानी देना होता है, उस में इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जो कि दूसरी मिनिस्ट्री के पास नहीं होते । न उन के पास किसी प्रोजेक्ट को टकनिकली एग्जामिन करने का इन्तजाम होता है और न वह उस को एग्जिक्यूट कर सकती हैं । खास तौर पर वह इलाके जहां पर माइनर इरिगेशन का काम आज कल हो रहा है, आज जहां पर उन की प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, वहां पर काम ऐसे ढंग से हो रहा है कि मालूम होता है कि बहुत कम काम हुआ है । मैं यह मान सकता हूं कि जो छोटे छोटे तालाब वगैरह हैं, जो कि आज कल किसी इलाके में चल रहे हैं वह मिनिस्ट्री आफ कम्यूनिटी डेवेलपमेंट को दिये जायें, लेकिन जो बड़े बड़े काम हैं, वह तो इसी मिनिस्ट्री के पास होने चाहिये ताकि उन कामों पर ज्यादा तवज्जह दी जा सके और उन कामों से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके । जहां तक सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन के टार्गेट का सवाल है, ४० लाख एकड़ के करीब माइनर इरिगेशन प्रोजेक्स का टार्गेट है । लेकिन इस सिलसिले में कागजी कार्रवाई चाहे जितनी हो, वह ५ या ७ लाख एकड से ज्यादा जमीन को पानी नहीं दे सकेंगे ।

इस के बाद मैं कुछ सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के बारे में कहना चाहता हूं । सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन ने जो काम इस देश में किया है वह सराहना और तारीफ के काबिल है । उन्होंने जिस ढंग से हिन्दुस्तान की तमाम प्रोजेक्टस को एग्जामिन किया है, जितनी इम्पार्शली इस काम को किया है, उन के टेकनिकल विंग ने जितनी राय दी है, या जितनी प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, हिन्दुस्तान के भीतर ही नहीं, बाहर भी उस की तारीफ हुई है । लेकिन जिस तरह से इस मिनिस्ट्री का काम बढ़ता जाता है, उस के साथ यह लाजिमी है कि सेंट्रल वाटर ऐंड पावर

[सरदार इकबाल सिंह]

कमिशन को और मजबूत किया जाय ताकि यह सब काम जल्दी हो सकें, यह सब काम अच्छे ढंग से हो सकें, हर प्रोजेक्ट्स अच्छे ढंग से एग्जामिन हो सकें और अगर उन में किसी

इस किस्म के नुक्स हों तो वह निकल सकें जिन प्राजेक्टस का इम्प्लिमेंटेशन हो उन को निगरानी अच्छे ढंग से हो सके। उस का मजबूत भी करना चाहिय और उस के साथ साथ उस को दो तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहिये । उन में से एक हिस्सा प्लैनिंग के साथ डील करे । आप जानते हैं कि आज कल हिन्दुस्तान में कितनी प्रीजेक्ट्स चल रही हैं । उन को पहले एक सूबे में बनाने के लिये तजवीज किया गया, फिर उसके बाद दूसरे सूब की सरकार ने यह कहा कि वहां के बजाय वहां इस को बनना चाहिये । फिर तीसरी स्टेट ने कहा कि नहीं यहां के बजाय यहां बनना चाहिये, इस लिये प्लेनिंग का जो हिस्सा हो उस को और ज्यादा मजबूत करना चाहिये । इस समय जो टेकनिकल एग्जामिनेशन होता है उस को भी सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन करता है, उसी में कुछ डाइरेक्टर्स बढ़ा कर तमाम स्कीम्स को अच्छे ढंग से एग्जामिन होना चाहिये, इस के लिये भी इस विंग को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ।

दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह इन्स्पेक्शन की है । आप जानते हैं कि आज कल कहीं पर भी ठीक इन्स्पेक्शन नहीं हो पाता है । अगर कोई स्कीम्स बनती है और उन में नुकायस रह गये तो उन पर रिपेअर रेशियो बहुत ज्यादा आता है और रिपेअर की कास्ट भी ज्यादा आती है । आज इस की बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं । स्कीमों काठीक से इन्स्पेक्शन न होने की वजह से उन में नुक्स रह गये और उनसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सका । पंजाब में एक ऐसी मिसाल हुई थी । भाखरा की नहर जिस दिन निकली, उस के नीचे का एक साइफन उसी दिन टूट गया, यह कोई पांच या छः साल पुराना किस्सा है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के अन्दर इन्स्पेक्शन अच्छा हो इसके लिये उस के मातहत एक इन्स्पेक्शन सेल या डाइरेक्टोरेट होना चाहिये । एक ऐसा इंडीपेन्डेंट विंग होना चाहिये जो देखे कि जो भी काम होता है वह स्टैन्डर्ड के मताबिक होता है, वह ठीक ढंग से होता है । आज इन्स्पेक्शन का काम भी उन इंजीनियर्स के पास है जिस के मुताल्लिक कहा गया कि एग्जिक्यूशन वालों के साथ उसे नहीं होना चाहिये । आज जो एग्जिक्यूशन का काम है वह भले ही सूबे की सरकारों के पास हो, लेकिन जो इन्स्पेक्शन का काम है वह सेंट्रल वाटर ऐंट पावर कमिशन के पास होना चाहिये और उस के इन्स्पेक्शन विंग को मजबूत कर के उस के पास रखना चाहिये । आज हिन्दुस्तान में कोई अदाद शुमार रिपेअर्स के बारे में नहीं मिल सकते । लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि पहले के बजाय आज जो रिपेअर रेशियो है जो नये बने हुए डैम्स हैं, नये बने हुये पुल हैं, नई बनी हुई नहरें हैं , उन पर बहुत ज्यादा है । इस लिये मैं यह चाहता हूं कि रिपेअर रेशियों को कम करने के लिये इस मिनिस्ट्री को और साधन ढूंढने चाहियें ताकि इस देश का जो रुपया है वह ठीक ढंग से खर्च हो, फाल्स एकानमी में खर्च न हो । यह न हो कि किसी इंजीनियर ने एक साल में कुछ रुपया बचा दिया है लेकिन उस से बड़ा नुक्सान हो जाय ५ या ६ लाख का । इस तरह से कोई फायदा देश का नहीं हो सकता है । इस लिये रिपेअर रेशियो पर इस मिनिस्ट्री को हर साल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में फिगर्स देने चाहियें ताकि यह पता

चल सके कि इस बारे में किस किस्म का काम किया गया है।

इस के बाद जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह कैनाल वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। इस वक्त दुनिया में और हिन्दुस्तान में कम से कम यह असर है कि कैनाल वाटर डिस्प्यूट हल होने को है। सब की यही ख्वाहिश है कि यह हल हो जाय ताकि जिन हिन्दुस्तान के लाखों, करोड़ों इन्सानों की जिन्दगी वाटर डिस्प्यूट के हल होने पर निर्भर करती है, उन की जिन्दगी में बेहतर दिन आ सकें। लेकिन जहां मैं यह आशा करता हूं वहां प्रैक्टिकल बात को देखते हुए मुझे आस्मान पर बादल नजर आते हैं। हिन्दुस्तान का केस मुझे इस किस्म का केस नजर आता है जैसे कि वह जहाज जो कि तूफान में हो और जिस के लंगर कट चुके हों, जिस को आगे नजर आता हो न पीछे नजर आता हो। जिन बातों पर हम अपने केस को मजबूत कर रहे हैं, सन् १९४८ का जो एग्रीमेंट था, मैं नहीं कहता कि हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके बजाय और बातें हिन्दुस्तान के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने और डिस्कशन में कुछ ज्यादा हुई। हिन्दुस्तान का जो केस था वह अच्छे ढंग से पुट नहीं किया जाता। जो इतना मजबूत ऐग्रिमेंट था, जिस में इतनी मजबूत बातें थीं और जिन पर पाकिस्तान की सरकार के चलाने वालों के दस्तखत थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत थे, उनके गवर्नर जेनरल के दस्तखत थे, आज उन बातों को छोड़ दिया गया है। आज हम बिल्कुल एक नई दुनिया में चलते हैं। मुझे आशा है कि ऐग्रिमेंट कामयाब हो जायेगा, लेकिन उस में मुझे कुछ शक नजर आता है। जिस ढंग से पाकिस्तान ने बंगलिंग की है इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट में मुझे नजर आता है कि वह लोग इस को दिल से हल नहीं करना चाहते। इसलिये हल नहीं करना चाहते कि उन की सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं वह इसी बात पर निर्भर करते हैं कि वह कश्मीर के मामले को, कैनाल वाटर डिस्प्यूट के मामले को चलाते रह कर अपने राज्य को कायम रख सकें, इस लिये नहीं कि उन को पाकिस्तान के लोगों से कुछ प्यार है, बल्कि इस लिये कि वह इस तरह के साइकालोजिकल ऐटमास्फियर के ऊपर जिन्दा रहना चाहते हैं। पहले यह चीज ६० करोड़ से शुरू हुई थी, लेकिन आज हिन्दुस्तान में और दुनिया में खबरें छपती हैं कि वह ८१ करोड़ तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान ने कुछ कदम तय कर लिये हैं। मेरी ख्वाहिश है कि यह मामला हल हो जाय, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी हल होते नजर नहीं आता। इस मामले में मैं एक बात जरूर चाहता हूं। जिस ढंग से हमारे पाटिल साहब ने दो साल पहले इस ऐलान में कहा था कि हम सन् १९६२ के बाद उनको पानी नहीं देंगे, आज माहतरम हाफिज साहब की तरफ से भी यह डिक्लेरेशन होना चाहिये। आज जबकि तमाम दुनिया में शक की निगाहें इस सिलसिले में उठ रही हैं, तो उनकी तरफ से इस का ऐलान होना जरूरी है। वाजे किस्म का एक ऐलान होना चाहिये। अब इन बातों में जो एक सीक्रेसी होती है तो मैं उससे इंकार नहीं करता और मैं मानता हूं कि उनके सम्बन्ध में कुछ सीक्रेसी हो सकती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान के जो सरकारी अखबार हैं उनमें इनके बारे में ज्यों की त्यों खबरें दी हुई हैं और इसके अलावा दुनिया के दीगर अखबारों में भी वे तमाम चीजें निकलती हैं। लन्दन एकानामिस्ट सारी की सारी स्कीम्स को पब्लिश कर देता है लेकिन हिन्दुस्तान के अखबारों में वह तमाम चीजें और स्कीम्स यह कर छापा नहीं की जाती हैं कि इसमें सीक्रेसी एनवौलव्ड है। अब मैं इसमें इंकार नहीं करता कि जो वार्कर में सीक्रेट स्कीम्स और चीजें हों उनको अखबारों में छापा न करें लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट के सिलसिले में इस बात को हमारी सरकार को

[सरदार इकबाल सिंह]

ध्यान में रखना चाहिये कि इसके बारे में जहां हमारे लोगों की यह जबर्दस्त ख्वाहिश है कि यह नहरी पानी विवाद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो चल रहा है यह शीघ्र सुलझे लेकिन उसी के साथ उनकी यह भी ख्वाहिश है कि यह विवाद ऐसे ढंग से हल हो जिसमें कि हिन्दुस्तान के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो और उनके हितों को किसी तरह की आंच न पहुंचे पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में समझौता करने के लिये गवर्नमेंट आफ इण्डिया को किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये क्योंकि इस बारे में हिन्दुस्तान का स्टैण्ड बिल्कुल सही और इंसाफ पर मबनी है। उसका स्टैंड मजबूत है और इसलिये उसको इस बारे में किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये। अब किसी जगह पर पोलिटिकल लेबिल पर भले ही कोई अन्य फैसला हो जाय लेकिन जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है और हमारे स्टैंड का ताल्लुक है वह चूंकि सही है इसलिये उसी आधार पर इस बारे में फैसला होना चाहिये और अन्य कोई फैसला हो नहीं सकता।

इसी सिलसिले में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस नहरी पानी विवाद का फैसला हो जाता है तो जो पानी बचेगा उसे काम में लाने के लिये कम से कम गवर्नमेंट आफ इण्डिया को जल्दी से जल्दी ऐसी स्कीमें बनानी चाहियें ताकि उस पानी को हम जल्दी से जल्दी इस्तैमाल कर सकें। सरहिन्द कैनाल फीडर को जल्दी से जल्दी मुकम्मिल करना चाहिये। इसी तरह राजस्थान कैनाल को भी जल्दी ही मुकम्मिल करना चाहिये। इसके अलावा ब्यास और धौन डैम्स को भी जल्दी से जल्दी मुकम्मिल करना चाहिये। यह सब काम करने सिर्फ इसीलिये जरूरी नहीं हैं कि हमारे हिस्से में जो पानी आये उसका फायदा हिन्दुस्तान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे बल्कि इसलिए भी यह काम जल्दी पूरे किये जाने चाहियें कि अगर उन स्कीमों पर हम इस नहरी पानी विवाद के फैसले के बाद काम करना शुरू करेंगे तो वह काम हल नहीं हो सकेगा और उसमें बहुत अधिक साल लग जायेंगे और इस तरह उस फैसले का हमें काफी लाभ नहीं हो सकेगा।

अब पंजाब और राजस्थान में बहुत छोटी छोटी स्कीमें हैं जिनको कि मुकम्मिल किया जाना बहुत जरूरी है और जैसे कि मैंने बताया सरहिन्द कैनाल फीडर और दादरी की स्कीमें हैं। उन तमाम स्कीमों पर और ज्यादा तेजी के साथ काम करना चाहिये ताकि जिस दिन भी इस बारे में फैसला हो तो जो पानी हमारे हिस्से में आये उस पानी का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें और लोगों की बेहतरी के लिये उसे इस्तेमाल में लाया जा सके।

इसके बाद मैं पंजाब की वाटर लौगिंग के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। जिस दिन पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बने थे तो पंजाब में ७ लाख एकड़ के करीब वाटर लौगिंग का इलाका था और जो कि हर साल २, ३ लाख एकड़ के करीब बढ़ता ही चला गया और आज पोजीशन यह है कि ३५ लाख के करीब वाटर लोग्ड एरिया है और ६, १० लाख एकड़ के करीब ऐसा इलाका है जहां पर कि पानी का लेविल ५ फुट से लेकर १० फुट तक है और हालत यह है कि बरसात के दिनों में वहां पर पानी का लेविल एक एक फुट और कहीं कहीं पर तो तीन तीन फुट तक तक हो जाता है और उस इलाके में फिर किसी किस्म की खेती नहीं हो सकती। इस तरह मैं समझता हूं कि पंजाब में कोई ४०, ४५ लाख एकड़ का इलाका वाटर लौग्ड है और जब तक कि आप इस मसले को मजबूती और तेजी से हल नहीं करेंगे तब तक पंजाब के उन वाटर लौग्ड एरिया को रिलीफ नहीं मिल सकेगी। अब पंजाब में पांच

प्रौजैक्ट्स मंजूर हुए हैं, फाजिल्का, जीरा, हांसी और तरनतारन और इन प्रौजैक्ट्स पर केन्द्रीय सरकार को ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये लेकिन खाली यह प्रौजैक्ट्स से ही सारा मामला हल होने वाला नहीं है । जब तक पंजाब के बाकी इलाके की वाटर लैविल आप दस फुट से नीचे नहीं लायेंगे तब तक वह इलाका खेती करने के लायक नहीं हो सकेगा । यह वाटर लौग्ड एरिया हर साल बढ़ता जाता है और इसके लिये मेरी गुजारिश है कि पंजाब गवर्नमेंट को ज्यादा रुपया देना चाहिय । एक बात यह भी है कि वाटर लौगिंग की स्कीमों को फ्लड्स कंट्रोल के साथ शामिल नहीं करना चाहिये क्योंकि यह मसला ही मुख्तलिफ है । इस मसले की बैक ग्राउण्ड ही मुख्तलिफ है । अब जो यह फ्लड्स आते हैं तो ५, १० या २० दिन के लिये लोगों को बहुत मुसीबत हो जाती है और वह मसला खत्म हो जाता है लेकिन वाटर लौगिंग का मसला एक परमानेंट मसला है । मैं खुद जानता हूं कि फीरोजपुर, अमृतसर, लुधिया, हिसार और संगरूर में एसी जगहें हैं जहां कि ५, ५ और ६, ६ साल से फसलें नहीं हुई । आप जान सकते हैं कि उन इलाकों के लोगों की क्या हालत होगी और उनकी एकोनामिक कंडीशन किस किस्म की होगी । उनमें भी सैकड़ों किस्म के तकावी लोन हैं । कुछ खश्रा साहब के हैं और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के हैं । फटिलाइजर्स के लौन हैं जब हमारी कैपेसिटी टु पे नहीं है तो हम दे तो कहां से । जिस इलाके में पिछले ३ या ४ या ६ सालों से फसल नहीं हुई तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उनके पास पैसा कहां से आ सकता है । मैं चाहता हूं कि इस वाटर लौगिंग के मसले को हल करने के लिये भविष्य की स्कीमें बनानी चाहिये और जो नहरें निकलती हैं उनमें एसे ढंग से पानी निकालना चाहिये कि वाटर लौगिंग का कम से कम खतरा हो । मैं भी कहता हूं कि जो आप राजस्थान कैनाल निकालने लगे हैं उससे खतरा है कि जिस इलाके में राजस्थान कैनाल जायगी उस इलाके में १० साल से लेकर १५ साल के अर्से में वाटर लेविल १५, २० फुट के पास हो जायगा । आज की एकोनामी को छोड़ कर अगर आप फ्यूचर के लिये उस नहर को प्लान नहीं करेंगे तो हालांकि वह नहर हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों के लिए फायदे मन्द साबित हो सकती है लेकिन इस वाटर लौगिंग की वजह से उन इलाकों में जहां कि वह जायगी लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होने का खतरा बना रहता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो नहरें हैं वे फ्यूचर के लिये इस तरह से प्लांड हों कि हमारे इंजीनियर्स जो कि मिश्र में गये हैं उन्होंने वहां पर देखा है कि मिश्र में दो किस्म की नहरें होती हैं । वहां पर डबल चैनल वाली नहर होती है एक चैनल से पानी आता है और दूसरी चैनल ड्रेन आफ करने के लिये होती है । मैं चाहता हूं कि यहां पर भी कुछ उस तरह का बन्दोबस्त किया जाय और इस तरह की डबल चैनल्स बनाई जायं ताकि एक से तो होकर खतों को पानी जाय और दूसरी चैनल से वह ड्रेन आफ हो सके और अगर ऐसी वाटर चैनल्स नहीं बनायेंगे और कैनाल्स के ड्रेनेज के लिये और कोई जरिया नहीं निकालेंगे तो वह इलाका १०, १५ साल के बाद वाटर लौग्ड हो जायगा और उस इलाके के लोग यह कहेंगे कि यह नहर हमारे फायदे के लिये लाई गई थी लेकिन अब हमें इनकी जरूरत नहीं क्योंकि इससे नुकसान अधिक हो रहा है और आप इन्हें उठा कर ले जाओ । ऐसे इलाके मौजूद है जहां पर कि लोग यह कहते हैं कि इस नहर की हमें कोई जरूरत नहीं है और इस नहर को बन्द कर दीजिये और इस नहर को उठा लीजिये । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि वाटर चैनल्स और वाटर लौगिंग की चैनल्स साथ साथ खोदी जायं जिससे कि पानी की सीपेज अच्छी तरह हो सके और पानी की जो लेविल है वह नीची रहे । इस तरह उस इलाके की खुशहाली भी कायम रक्खी जा सकती है और उस इलाके के लोगों को वाटर लौगिंग का भी खतरा नहीं हो सकता है । अब पंजाब गवर्नमेंट को फ्लड्स कंट्रोल और वाटर

[सरदार इकबाल सिंह]

लौगिंग के सिलसिले में पांच सालों में ३ करोड़ ६५ लाख रुपया मिला है । वह रुपया तकरीबन उन्होंने खर्च कर लिया है । पिछले साल एक करोड़ रुपया मिला था वह इस साल तक दिया जायगा और कुछ रुपया उनको और मिलेगा जो कि शायद ६ महीने में पहुंचना था । परमानेंट बेसिस पर पंजाब को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देनी चाहिये । इस तरह की ऐडहोक ग्रांट्स से इनको पूरा फायदा नहीं हो सकता । एक स्कीम चलती है पांच, दस साल में वह चैनल्स बन्द हो जाती है । अगली बरसात में वह चैनल्स की चैनल्स खराब हो जाती हैं और उनका कोई फायदा नहीं हो सकता ।उस पर बहुत सा खर्चा आता है । कहीं पर पुल बनाने होते हैं, कहीं पर नहर के पुल बनाने होते हैं, कहीं नहर के नीचे से, कहीं नहर के ऊपर से पुल बनाने होते हैं । कहीं रेल की पटरी के पुल बनाने होते हैं । वह नहीं बन पाते । बहुत जगह हमने देखा है कि इन एडहाक ग्राण्ट्स से नुकसान ज्यादा हुआ है । इसलिये इस के वास्ते परमानेंट स्कीम होनी चाहिये और पंजाब गवर्नमेंट को परमानेंट ग्राण्ट देनी चाहिये । अब तक आप तीसरी प्लान में पंजाब को दो करोड़ या तीन करोड़ की परमानेंट ग्राण्ट नहीं देंगे तब तक पंजाब का वाटर लागिंग का मसला हल नहीं हो सकता ।

इसके अलावा मैं फ्लड कंट्रोल के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं । एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डिफरेंट हैड्स होने चाहियें इनकी स्कीमों का अलाहिदा अलाहिदा एग्जीक्यूशन होना चाहिय, पंजाब को या दूसरे सूबों को जो रुपया फ्लड कंट्रोल के लिये मिलता है, अगर प्लानिंग कमीशन को कट लगाना होता है तो सबसे पहले इस किस्म की स्कीमों पर कट लगाया जाता है । इस सिलसिले में मैं मिनिस्ट्री से यह कहना चाहता हूं कि उसको प्लानिंग कमीशन के आगे अपने केस को मजबूती के साथ प्लीड करना चाहिय कि इस स्कीम पर कट न लगाय जायें और जो कट हुआ है उसको रेस्टोर होने के बाद थर्ड प्लान में इस काम के लिय पूरा रुपया मिलना चाहिय, ताकि जिन इलाकों में फ्लड का खतरा रहता है वहां हमेशा के लिय कोई न कोई बन्दोबस्त किया जा सके ।

17 hrs.

इसके बाद मैं बिजली के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं । पंजाब में और बहुत सी स्टेटों में आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाये है । मैं समझता हूं यह ठीक काम है । लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डील करना होता है लोगों के साथ । लेकिन अगर आप किसी मैशिनरी को बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक बना देते है और सिर्फ यही देखते हैं कि इससे कितना पैसा आता है, तो उस मशीनरी से आम लोगों को पूरा फायदा नहीं पहुंच सकता । आप यह कह सकते है कि हमने ५ पर सेंट नफा दिखाया, या १० पर सेंट नफा दिखाया या ६ परसेंट या ७ पर सेंट नफा दिखाया, लेकिन आम लोगों के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता । और दूसरी बात यह है कि जो स्टेटों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनमें यह रिवाज होता चला जाता है कि वह बड़ी बड़ी फैक्टरियों में से किसी एक को बल्क सप्लाई कर देते हैं और उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है । वह यह देखना गवारा नहीं करते कि इस देश में गांव हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, छोटे छोटे दस्तकार हैं । अगर यही बिजली उनको दी जायें तो हजारों आदमियों को एम्प्लायमेंट मिल सकता है । हजारों घरों में रोशनी हो सकती है । इसके बजाये वह यह करते हैं कि जैसे पंजाब में नगल फरटीलाइजर फैक्टरी को और उत्तर प्रदेश में रिहन्द एल्यूमीनियम फैक्टरी को बिजली दे देते हैं ताकि प्लानिंग कमीशन को कह सकें कि पंजाब को जो ३० करोड़ रुपया मिला उसपर हमने ५ पर सेंट नफा किया , या ४० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला उस पर हमने इतने परसेंट नफा किया । मैं मानता हूं कि ये चीजें जरूरी हैं लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी वह है जो छोटी छोटी दस्तकारी करने वाले आदमी है, ज्यादा बिजली मिलनी चाहिय और यह तभी उनमें

हो सकता है जब कि स्टेटों के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं इनमें कुछ तबदीली की जाय । इस वक्त ये पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक हैं, ये किसी के नीचे नहीं हैं, इन पर पबलिक ओपीनियन का कोई असर नहीं होता, इनको सलाह देने के लिये कोई एडवाइजरी बाडी नहीं है, एम० एल० एज० को कंसल्ट नहीं किया जाता । यह एक डिपार्टमेंट है जो कि कम्पनी की तरह बनकर रह गया है । मैं यह समझ सकता हूं कि अगर हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी काफी मशीन टूल न बनाये तो हिन्दुस्तान को नुकसान होगा, लेकिन जो बिजली का महकमा है उससे लोगों का काम पड़ता है । आप जानते हैं कि आज कितने गांव इस बात पर आशा लगाये बैठे हैं कि कब हमारे गांव में बिजली आयेगी, कितने किसान हैं जो कि इस बात पर आशा लगाये बैठ हैं कि उन्हें बिजली मिलेगी और उनके ट्यूब वैल चलेंगे, उनकी खेती अच्छी होगी और इस तरह से उनकी आमदनी बढ़गी । कितने आदमी इस बात पर आशा लगाये बैठे है कि उनके दस्तकारी के छोटे छोटे काम बिजली से चलेंगे । ये लोग इस ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते । उनको उसमें कहीं जगह नहीं मिल पाती । वह कहते है कि इस गांव में बिजली तब लायी जायेगी जब पांच पर सेंट मुनाफा मिले । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ पबलिक ओपीनियन को शामिल करें । और जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स हैं और जिनके लिये सेंटर ग्रांट देता है, उसमें आप देखें कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले । देहात के आदमी बिजली, पानी और सड़क पर आशा रखते हैं । अगर उनको ये तीन चीजें नहीं मिलती तो स्वराज्य की आशायें उनके दिल में कमजोर हो जाती हैं और वह निराश हो जाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम्स है उनके साथ हर जगह पबलिक एड-वाइजरी बाडीज को शामिल किया जाये और एक ही बड़े कारखाने को या एक ही आदमी को ज्यादा तादाद में बिजली देने की टेंडेंसी को रोका जाये ।

आप पंजाब की बात जानते हैं । हमें आशा थी कि पंजाब में इतनी ज्यादा बिजली होगी लेकिन आज जो बिजली पंजाब में पैदा होती है उसमें से ज्यादातर बिजली दिल्ली को और राजस्थान को चली जाती है । राजस्थान के लिये हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि उनको भी हमारी तरह जरूरत है । लेकिन दिल्ली तो अमीर है । उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है । मैं कहता हूं कि पंजाब के आदमियों को बिजली की जितनी शार्टेज है उतनी और किसी सूबे में नहीं है । इसका एक ही हल है कि आप भाखरा डैम पर एक और पावर हाउस बनायें और कोटला और गंगूवाल में जल्दी से जल्दी बिजलीघर लगायें । इसका तीसरा हल यह है कि पंजाब में न्यूकलियर पावर स्टेशन जरूर होना चाहिये । पंजाब के लोग मेहनती हैं, और छोटी दस्तकारी वहां फैले इसके लिये जरूरी है कि आप वहां ज्यादा बिजली दें । वहां बड़े कारखाने जैसे भिलाई और रूरकेला तो लग नहीं सकते लेकिन वहां छोटे कारखाने तो लग सकते हैं । वहां जो छोटे मेहनती आदमी हैं, उनको आप जब तक ज्यादा बिजली नहीं देंगे तब तक पंजाब कभी खुशहाल नहीं हो सकता । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो स्कीमें मैंने बतलायी हैं उनको आप हाथ में लें । इस के अलावा श्याम लिक की स्कीम है, उस पर भी जल्दी काम शुरू किया जाना चाहिय । जितनी बिजली श्याम लिक की की स्कीम से पैदा होगी उतनी हिन्दुस्तान में किसी एक स्कीम से नहीं होगी । इसलिये इस स्कीम को आप हाथ में लें । मैं इसमें आपसे इलतिफाक कर सकता हूं कि इसको हिस्सों में लें, किसी हिस्से को पांच साल में बनावें, दूसरे को आयन्दा पांच साल में बनावें । लेकिन इसको सेंक्शन करके इस पर जल्द काम शुरू होना चाहिये ताकि पंजाब को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके ।

आजकल हिन्दुस्तान में यह हो रहा है कि जहां आपकी नहरें जाती है वहां किसान पानी लेने के लिये तैयार नहीं होते । इसका एक ही हल है । पंजाब के भाई इस चीज को जानते हैं

[सरदार इकबाल सिंह]

क्योंकि वह उस इलाके से आते हैं जहां नहरों का सिस्टम बहुत सालों से है। जब तक आप नहरों से चैनल बनाकर किसान के खेत तक पानी ले जाने का इन्तिजाम नहीं करेंगे तब तक किसान इस पानी को नहीं लेगा क्योंकि वह दूर से पानी लाने के लिये चैनल अपने आप नहीं बना सकता। पंजाब में तो चालीस पचास साल से इर्रीगेशन का काम हो रहा है, लेकिन अगर किसी आदमी को ५०० गज चैनल ले जाना हो तो वह नहीं ले जा सकता। यह हालत तो पंजाब की है जहां कि लोग यह जानते हैं इस पानी से उनकी खेती की कितनी बेहतरी हो सकती है। तो आप जब तक चैनल्स का इन्तिजाम नहीं करेंगे तब तक आपका सिंचाई का टारगेट पूरा नहीं हो सकता।

आखिरी बात मैं ट्यूब वैल्स के सिलसिले में कहना चाहता हूं। आपने जो ट्यूब वैल लगाये उनमें से बहुत से चल नहीं सके। पंजाब में भी नहीं चले और यू० पी० में भी नहीं चले। प्लानिंग कमीशन ने इस सिलसिले में एन्क्वायरी करने के लिये एक कमेटी बनायी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि यू० पी० में कुछ ट्यूब वैल साल में डेढ़ दिन चले और पंजाब में कुछ साल में पांच सात दिन चले, कोई १६ दिन चले, कोई २५ दिन चले। इसका डिफरेंट डाटा उस रिपोर्ट में दिया गया है, पता नहीं वह अभी पबलिश हुई या नहीं। इसकी वजह यह है कि ट्यूब वैल्स की प्लानिंग गलत की गयी। जब तक आप ट्यूब वैल्स के लिये पक्की चैनल्स नहीं बनायेंगे तब तक उनसे फायदा नहीं हो सकता। ट्यूब वैल्स इसलिये भी ज्यादा फायदेमन्द हैं कि वे वाटर लैवल को नीचे लाते हैं। अगर ट्यूब वैल्ज को एक इकानोमिक प्रापोजीशन के तौर पर सोचेंगे, तो वे बहुत कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो ट्यूब वैल गवर्नमेंट लगाती है, वे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। प्राइवेट एन्टरप्राइजर या किसान अपने तौर पर ट्यूब वैल बहुत सस्ता लगा सकता है। इसलिये गवर्नमेंट को सबसिडी देनी चाहिये और ट्यूब वैल्ज के सिलसिले में एक अच्छी स्कीम बनानी चाहिये, जिस के मुताबिक ट्यूब वैल सबसीडाइज्ड रेट पर लगाये जा सकें, ताकि वाटर-लैवल नीचे लाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं मिनिस्ट्री की डिमांड्ज की हिमायत करता हूं।

Shri Halder (Diamond Harbour—Reserved—Sch. Castes): Mr. Deputy-Speaker, the Ministry of Irrigation and Power is supposed to help in producing plenty and throwing light into the dark houses of the teaming millions. The Ministry's function is to irrigate land so that our food problem can be solved; it has also to control floods which off and on cause havoc in various parts of our country, rendering thousands of people homeless, and then it has to generate power to industriallse the country.

But their activities present an appalling picture. The projects of DVC and Bhakra are the projects of successful bungling in every respect, whether of accounting, construction or utility. These can be called monuments of bungling *par excellence*.

It is not possible within the short time at my disposal to go into the activities of this Ministry on various aspects, and as such, I shall deal with one aspect of its activities only, namely, the DVC. The people of West Bengal expected much from the DVC scheme. But to their utter dismay, they are totally frustrated by the activities of the Government. The scheme did not help to remove the danger of flood, but has aggravated it. The two catastrophic floods of 1956 and 1959 have shattered the sense of security in the matter of recurrence of flood in this State. In 1959, 11 districts out of 15 of the State were affected by flood and water logging. The total crop area damaged was 2,364 square miles, that is, about 13 per cent of the crop area of the dis-

tricts. Over 54 lakhs of people became victims of flood havoc, out of which 3,74,375 had to be rescued and provided with shelter. The loss of *aman* crop was 5.23 million tons. The number of dwelling houses destroyed and damaged was 5,04,468. The total loss was estimated to be nearly Rs. 100 crores. In the 1956 flood, the estimated loss was of the order of Rs. 11 crores.

A careful analysis of the two floods of 1956 and 1959 will show that both the depth and duration of the floods are increasing through long neglect and wrong measures. It is not nature's freak but human frailty which is mainly responsible for the disaster.

It cannot be denied that the flood discharge capacity of the Mayurakshi channel has deteriorated considerably during these years. The Government tries to escape from all responsibility by saying that the Mayurakshi scheme is not a flood control scheme. But it should not act as a flood producing scheme.

All other minor rivers and drainage channels have deteriorated and have been silted up through long years of neglect by the alien rulers. After independence, the Government has done nothing to resusitate them with the result that they cannot drain off the rain water, and a slightly heavy rainfall inundates the surrounding areas.

The Bhagirathi, the main outfall of the southern Bengal region, has also deteriorated considerably during the last few decades. Want of discharging capacity in the Bhagirathi is causing water logging in vast areas within Murshidabad, Nadia, Burdwan and Hooghly in the lower Damodar area.

The D.V.C. and Mayurakshi scheme instead of altering the *status ante* for the better, have made the situation worse. On the one hand, they have created further obstacles to drainage by raising a network of canal embankments in all directions throughout the length and breadth of the country without providing adequate water passage; but, on the other hand, they are discharging a considerable volume of water through irrigation canal . . .

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): Sir, I have no objection if the hon. Member goes on reading. But we cannot hear because he is not facing the mike. That is the difficulty. He is not at all audible here; and we do not follow him. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member can come forward; He can come to my seat. In fact, I am offering it to him.

Shri Halder: They discharge water that swells all the drainage channels of the area and quick drainage of this augmented volume of water has been a very serious problem.

Calcutta is the metropolitan city and the most important part of the country. So, its importance in our economy need not be emphasised. The solution of the serious drainage problem the city proper in particular and of great Calcutta in general is therefore of vital importance. The problem must be treated on a footing of national emergency.

The area of Greater Calcutta which includes the area east of the river Hooghly, a large portion of which is the 24 Paraganas District, including a portion of the Sundarbans and Nadia district, is 1,750 sq. miles.

Almost the whole of Sunderbans from Budge Budge to the Bay of Bengal were over-flooded during the heavy rainfall of 1959. Some portion of this city was submerged for several days. On the other hand, a vast area surrounding Calcutta is a vast water-logged one. The water-logged area is thus gradually increasing day by

[Shri Halder]

day. The area of the 24 Paraganas district is 5,639·6 sq. miles of which 3,000 and odd sq. miles form part of Sunderbans.

Sunderbans is a typical new deltaic formation. It is a network of tidal rivers, creeks and islands. The islands to the north, which are embanked, grow rich crops of rice. But, during the last rainfall almost the whole of Sunderbans was submerged and the area which was once a granary of West Bengal has become a deficit area.

Unlike other districts of West Bengal, the 24 Paraganas district requires little necessity for irrigation. Cultivation in this district, as a whole, suffers frequently from rainfall rather than from deficit rainfall.

15.19 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

The problem of food in the 24 Parganas is entirely a problem of drainage. Flood occurs not because of a sudden onrush of a heavy volume of upland water, but mainly due to local rainfall.

Hooghly river is the life-line not only of this district but of the State as a whole. But due to criminal negligence in tackling the urgent problem connected with the river, it has been deteriorating very fast in the past ten years. The Flood Enquiry Committee of 1956 warned that the deteriorating of the drainage capacity of the river has been 'very rapid' and due to the deteriorating of the river bed local drainage cannot function properly and it caused water-logging. The silting of the Khals, which constitutes vital drainage outlets of the districts, had posed a great problem.

The great city of Calcutta is now in the point of danger. It is not only that a big port is going to be useless because the river is being silted up day by day. Even the shipping companies in a Press conference recently drew the attention of the Government to the dangers of the Calcutta port and requested the Government to take immediate steps. Even before Independence, the British banias seeing the gradual silting of Hooghly planned to excavate a deep canal from Diamond Harbour to Khidirpur dock so that the big vessels can ply up to that great city easily. But after Independence the Government did not take any major steps for revival of this city. In this connection I may say that in West Bengal cities such as Murshidabad—Tamluk were destroyed due to silting by these rivers by the Ganges and the other rivers.

The workers of the D.V.C. and the Hirakud Dams who worked and built such big dams are being turned out after several years of work without alternative jobs. Government should take immediate steps so that they can get appointments without delay in other schemes.

I shall mention only one point regarding the water-logged area near Calcutta and its suburbs. During the last monsoon, due to heavy rainfall vast areas of West Bengal, particularly in the 24 paraganas district, were flooded. Some portion of these areas are still flooded. There are so many canals which could be used for irrigating but which are not taken up by the Government.

As a result of this the area has deteriorated so much that people from this area are coming to Calcutta in search of jobs.

We expect from the Ministry of Irrigation and Power big or small irrigation schemes in this area so that sufficient quantity of food is produced. The food situation in Bengal is gradually becoming bad. During this period the food prices in West Bengal are gradually rising. The

Government should take up irrigation and power projects in this area. They should take immediate steps to see that such devastating floods do not occur this year also making thousands of people homeless and shelterless.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Shri Naldurgkar—if he is not there, Shri Jena. There are some hon. Members who have not spoken at all.

Shri Khushwaqt Rai Kheri): Sir here is also another hon. Member who has not spoken so far.

Mr. Speaker: I shall call him also. All the hon. Members so far as I am concerned, those who have spoken and those who have not spoken.

Shri Khushwaqt Rai: I would request you, Sir, to extend the time.

Shri Speaker: It is too early.

Shri Naldurgkar: (Osmanabad): Mr. Speaker, Sir, I want to review the progress made by this Ministry during this decade. According to the figures available, there are nearly 80 crores acres in our country out of which 70 crore acres can be brought under cultivation. After excluding the total acreage that can be brought under forests and excluding the land that is uncultivable, above 70 crore acres can be brought under cultivation.

Now, when such a vast acreage can be brought under cultivation, we have to see whether we are making any progress or not. That is the main question. I am of the view that the progress of this department lacks in one respect. When we review the agricultural progress made in any other country, we find that the agriculturists are compelled to avail of water or irrigation facilities available as far as possible. From that point of view, in our country we are not taking this sort of steps. For instance, there are certain lands on the banks of certain rivulets or *nallahs*, as we call in our country. There are some irrigation facilities available on the banks of those rivulets or rivers. The agriculturists who own land on the bank of those rivulets or rivers are compelled to construct a bund. If that is not done by the agriculturists, then it is done by the gram panchayats. If it is not done by gram panchayats, then the Government constructs that bund and all those charges are recovered from the village. This step has not been as yet taken by our Government. In this respect, I want to suggest to the Minister to advise the State Governments, because the main object of the gram panchayats is the same. When 70 crore acres are under cultivation or can be brought under cultivation, then, according to me, there is no question of the production of other countries exceeding ours, or of our need to import from abroad. If the whole acreage can be brought under cultivation, that will increase our food supplies.

So, there are two aspects to be taken into consideration. One is the traditional agriculturist. By tradition, our country is an agricultural country. We have to do two things. We have to maintain the agricultural standard, that is to say, the standards of the traditional agriculturists. Then, we have to create another class of agriculturists, namely, the created agriculturists, as against the born or the traditional agriculturists. "Created agriculturists" means those agriculturists who would be given lands after reclamation.

There is also one defect. During the past decade, only 25 lakh acres have been reclaimed. Not more than that. The progress therefore has been very slow as far as our reclamation programme is concerned. When the lands are given to certain persons who are peasants or who may come under what is called co-operatives, whatever it may be, then those agriculturists become created agriculturists. They are agriculturists who are created, and to them the land, the implements and all the paraphernalia of

[Shri Naldurgkar]

agriculture have to be given for cultivation. Otherwise, they cannot do anything.

In my own constituency, some lands were allotted to the Harijans. It was done in Badagaon village, in my own district. But I am sorry to say that afterwards the Government did not take any interest. The Harijans became quite helpless. They had no bullocks or any implements to proceed with cultivation. Therefore, in spite of the fact that there was a co-operative society which was formed, they could not do anything. So, my point is, when gram panchayats have been already established, the main object must be this. It should be the duty of the irrigation departments to instruct all the gram panchayats to erect bunds on all *nallahs* and small rivulets. If that is not done by the gram panchayats, it will be duty of the Government to construct the bunds and recover the costs from the gram panchayats and other responsible persons concerned with the work.

My second point is this. When we read the literature of other countries, what do we find? There is one thing which is apparent in this connection. As far as our agriculture reports, irrigation reports and community development reports, etc., are concerned, there are certain experts and expert committees that we find in regard to these things. In other countries also, we find a number of expert committees. The committee is entrusted with the work or scrutinising or examining the soil of the land, that is to say, the power of fertility. Fertility or the power of fertility is examined and then it is decided what sort of crop can be grown on the land. We have been doing certain things by way of tradition. But such experiments through expert committees have been successfully worked out in other countries. Suppose, if a certain piece of land can be suitable for, say, groundnut production alone, then, our people will grow groundnut alone on that land because of the tradition. On those lands which are capable of yielding *rabi* crop or *kharif* crop no other crop will be grown. But that is a wrong impression.

In other countries, experiments have been made and after conducting an examination or scrutiny of the fertility of the soil, it is proved by the experts, and it is declared by them that such and such a land is capable of giving such and such production. Then, improved seeds are made available to the agriculturists. So, in that way, a nation can progress. I am referring to all these matters because irrigation and community development and agriculture are all departments on which the production of our country depends. Though the Ministries are separate, they are all interlinked with each other so far as production is concerned.

I should mention one thing in this respect. As far as irrigation is concerned, there is another difficulty. Whether in my constituency or in other places, there are a large number of projects big and small, but there is no mention in the report as to how far the land that was brought under irrigation has been utilised by the agriculturist. The report is silent on that point. The House must know, within the past decade when various projects have already been constructed, how much land was actually brought under irrigation by the agriculturist. That has not been mentioned anywhere. Unless that is done, irrigation is not doing its duty to the country. The main object of irrigation is not only to raise irrigation facilities and power to beautify the country. The main object of irrigation is, every agriculturist whose land can be brought under irrigation must utilise it for himself. If that is not done, compulsion must be imposed on him to do so. That is the object of irrigation.

I would respectfully submit that this step has not been taken either

by the Central or State Government. That is the main reason why there is scarcity of food in this country. If this step can be taken, I am convinced that agricultural production of the country will increase and the food problem can be solved to a great extent.

There is another thing as far as construction of projects is concerned. I am referring to Marathwada. Some days before, I had gone to see Purna project, which is the major project in Marathwada. It will cost nearly Rs. 13 crores and more than 1 lakh acres will be brought under irrigation. On one side there will be power generation and on another side irrigation. When I went there actually to see why the construction of the project is being delayed, I found nearly all the bulldozers were lying idle. I enquired the reason. I came to know that some tyres and other parts of the bulldozers were to be imported from another country and they were not available in our country. I enquired why they were not imported. Then I came to know that the Controller of Import and Export has not issued the licence. After that, I went personally to the Controller of Import and Export and submitted to him my little request. But after that, no reply has been given to me up to this time.

When a Member of Parliament approaches personally a certain authority and brings to his notice certain facts due to which a certain irrigation project has been delayed—not due to the fault of the executing authority, but due to the fault of a higher authority in not issuing the licence, in such cases, it is the duty of every officer to give a reply to the Member of Parliament. I think it is against the dignity of the Member of Parliament that a reply is not sent to him. Therefore, I would request the hon. Minister to take steps henceforward to see that whenever a Member of Parliament sends any request or any application or asks for any sort of information to the highest authority, it is the first duty of the authority to send a reply to him. Otherwise, it must be considered derogatory to the dignity of Parliament. These are some of the reasons why construction works are delayed.

In this respect, I want to say something about minor irrigation works in Marathawada. Construction of minor irrigation work has also been delayed due to a variety of reasons. Because of this delay, there is waste of money and time. Also, we are not able to achieve our targets. These are some of the defects and I hope the hon. Minister will take into consideration some of the suggestions that I have made.

Then, some hon. Members have referred to the canal water dispute between India and Pakistan. Some time back, when Shri S. K. Patil was the Irrigation Minister, he made a categorical statement in the House that after 1962 water supply to Pakistan will be stopped. Now, after reading the newspaper reports and some information given in this House it is seen that even after that date water will be supplied to Pakistan. I do not know why there should be two contradictory statements on the same subject. My opinion is that the water dispute between India and Pakistan should either be amicably settled before 1962, or if Pakistan is trying to intimidate us in such a way as to affect our progress in this matter, then it will be our duty to adhere to our own statement, as given in this Parliament by Shri S. K. Patil. This is one of the important matters that should be taken into consideration soon.

Then there is the important question of electrification of villages. Some statement has been issued on that by the Ministry and according to that nearly 8,000 villages have been electrified so far. I think the speed with which we are proceeding is very slow. As far as Bombay State is concerned, only 461 villages have been brought under electrification. Even there, the names of the villages and their popu-

[Shri Naldurgkar]

lation have not been given here. I am of the view that electrification of the villages should be done through gram panchayats where there are gram panchayats and by responsible members of the public in other villages and that they should be taken into confidence. Then only will we be able to progress and march forward.

I hope the Minister will look into the irrigation projects which are under construction and the electrification programmes and see to it that they are not delayed.

श्री का० च० जेना (बालासौर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं ।

श्री का० च० जेना : इस स्थिति में मुझे यह बात याद आती है—

बरं बने व्याघ्र गजेन्द्र सेवितं
न बन्धुमध्ये धनहीन जीवितव्यं ।

स्वतंत्रता के बाद जिन देशों के साथ हमारी बन्धुता हुई है, हम सोचते हैं कि वे हम से धनी हैं और अगर हम सोचते हैं कि उनके साथ हम को बन्धुता करनी हो, तो हमको उन्हीं की स्थिति पर जाना होगा, नहीं तो उनके साथ हमारी बन्धुता कायम नहीं रहेगी और वे हम को जरा छोटा समझेंगे ।

इस बात को कहने के समय मुझे यह बात याद आती है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना हो, धनी बनना हो, उन्नति करनी हो, तो वह बात दो ही चीजों पर निर्भर करती है । वे दो चीजें हैं उद्योग और कृषि । इन दोनों चीजों के सुधार इनकी उन्नति का उत्तरदायित्व मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एंड पावर पर ज्यादा है, जिसके अनुदानों पर हम विचार कर रहे हैं । मैं खास कर एग्रीकल्चर–कृषि–की बात कहता हूं । अगर हम कृषि के सुधार की ओर ज्यादा ध्यान दें, तो अन्न के विषय में हम जल्दी आत्म निर्भर हो सकेंगे । हम बड़ी बड़ी योजनाओं को लेते हैं, उन पर ज्यादा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उनसे लाभ हमें जल्दी नहीं मिलता है । मैं यह नहीं कहता कि इससे हमारा नुक्सान होता है । नुक्सान कभी नहीं होता है । ये प्रोजेक्ट्स मल्टी परपज हैं । इनसे ज्यादा लाभ होगा, लेकिन वह लाभ जल्दी नहीं होता है । अगर हम को लाभ जल्दी प्राप्त करना हो, तो बड़े बड़े प्राजेक्ट्स–योजनाओं–के साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं को भी अगर हम लेंगे, तो काम जल्दी होगा और खाद्य के विषय में हम जल्दी से जल्दी आत्म निर्भर हो सकेंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी को हीराकुड प्राजेक्ट के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे हमारी करीब चार लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी इस प्राजेक्ट से हमें जो इलेक्ट्रीसिटी मिलती है, उससे हमारा राउरकेला प्राजेक्ट चलता है और दूसरे प्राजेक्ट भी चलेंगे । माननीय मंत्री जी हर वक्त कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की दिक्कत से हम माचकुंड योजना को व्यवहार में नहीं ला सकते हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कोशिश करें कि इस दिक्कत को सुलझा कर माचकुंड योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करें ।

कृषि की उन्नति के लिये हमको—खासकर उड़ीसा को—पहले वन्या को कंट्रोल करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ नदी के ऊपर डम बनाने से वन्या कंट्रोल हो जायेगा । वन्या कंट्रोल दो तरीके का होता है —एक तो डम के द्वारा और दूसरा ड्रेनेज के द्वारा । जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा है, डैम तो जरूर बनाये जायें, लेकिन जहां पानी ज्यादा दिन तक रह कर फसल को सड़ा देता है, नुक्सान पहुंचा कर बरबाद कर देता है, इस बात का इन्तजाम करना

चाहिये कि वहां से वह पानी निकाल कर कैसे समुद्र में जल्दी से जल्दी डाला जाये ।

समुद्र के किनारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है कि समुद्र का पानी उमड़ते हुये जमीन में चला जाता है । उस से फसल नष्ट हो जाती है और सैलाइन वाटर की वजह से जमीन इतनी खराब हो जाती है, कई साल के लिये वह इतनी बरबाद हो जाती है कि वहां कोई आमदनी नहीं होती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा कोशिश करें कि सैलाइन इननडेशन को कैसे रोका जाये और इसके लिये वह प्रबन्ध करें ।

अब मैं बालासौर जिले की बात कहना चाहता हूं । वहां वैतरणी नदी का डैम के लिये प्रारम्भिक अनुसंधान हो रहा है । जो सालन्दी डैम बनने वाला था, वह वैतरणी पर निर्भर है, इस लिये वह रोका गया । इसी के साथ साथ बालासौर में एक इंटरस्टेट रिवर, एक इंटर प्राविशियल रिवर सुवर्णरेखा है, जिस से तीन सूबों का संबंध है । वे सूबे हैं : बिहार, बंगाल और उड़ीसा । यह नदी बिहार से निकलती हुई उड़ीसा में जाकर समुद्र में पड़ती है । यह नदी अपनी धारा को परिवर्तित करती है, लोगों को बेघरबार करती है और फसलों को नष्ट कर देती है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई एक्सपर्ट वहां भेज कर उस नदी का अनुसंधान करायें, नहीं तो दो तीन साल में ऐसा देखा जायेगा कि वह कई हजार आदमियों को बेघरबार कर देगी । इस संबंध में मुझे याद आता है कि पिछली दफा जब मैं उड़ीसा गया था, तो देखा कि शायद दो चार सौ घर हरिजन लोग, जिन के घरबार नदी में चले गये थे, आज कल इधर उधर पेड़ों के नीचे या किसी के बरामदे के नीचे रहते हैं, जहां सरकार की जमीन है वहां झोंपड़ी बना कर कुछ रोज ठहरते हैं । उन को वहां से यह कह कर भगा देते हैं कि तुम इधर से चले जाओ, यह हमारी जमीन है—सरकार की है, इसलिये गांव वालों की है । इस कारण वे इधर उधर घूमते फिरते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक्सपर्ट भेज कर नदी का कुछ अनुसंधान करायें कि क्या करने से वह अपनी गति को इतनी जल्दी परिवर्तित न करे ।

मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहूंगा कि अगर हम देहात की उन्नति चाहते हैं, तो तो हम को वहां छोटे छोटे धंधे देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी । आजकल बिजली का युग है । छोटे छोटे धंधों के लिये भी इलैक्ट्रिसिटी की जरूरत है । उस जरूरत को पूरा करने के लिये हमें हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, लेकिन वह जल्दी नहीं मिल सकती । इसलिये हमको थर्मल स्टेशन चाहिये । अगर हम थर्मल स्टेशन बनायें, तो हम को बिजली जल्दी मिल सकती है और हम छोटे छोटे धंधे खोल सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको छोटे छोटे धंधों में लगाने के लिये—सब समय खेती का काम नहीं होता है और जिस समय वे खाली बैठे रहते हैं, उस समय छोटे छोटे धंधों के लिये—बिजली मिल जाये, इस तरफ़ वह ध्यान दें ।

सुवर्ण रेखा के बारे में मैंने कहा है कि उसको कैसे डैम किया जाये, इस तरफ ध्यान दिया जाये । जैसा कि मैंने अभी कहा है, उसका सम्बन्ध तीन स्टेट्स—बिहार, बंगाल और उड़ीसा—से है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन तीनों स्टेट्स के साथ बातचीत करके उस नदी को डैम करने के बारे में कार्यवाही करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मिनिस्ट्री के अनुदानों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स

[श्री राम शंकर लाल]

पर बोलने का अवसर दिया है । इस विभाग का खेती से बहुत बड़ा सम्बन्ध है । आप जानते ही हैं आजकल हमारे मुल्क की एक खास समस्या है, जो गल्ले की समस्या है, समस्या यह है कि मुल्क को खाना मिलना चाहिये और गल्ला अधिक पैदा करने के लिये सिंचाई का होना बहुत जरूरी है, और सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध यह विभाग ही कर सकता है । अभी तक जो प्रयास हुआ है उससे ऐसी हालत पैदा नहीं हुई है कि हमारे मुल्क में पानी के अभाव के कारण जो सूखा पड़ता है, और खास तौर से मेरे हल्के में जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कहलाता है, वह रुक सके । पूर्वी उत्तर प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, वहां की आबादी बहुत अधिक है । उसमें पांच जिले आते हैं और किसी किसी जिले में एक मुरब्बा मील में एक हजार से भी अधिक की आबादी है । वहां पर रोजगार के अवसर भी अधिक नहीं हैं । वहां के लोग ज्यादा तर खेती पर ही निर्भर करते हैं । खेती का वहां पर यह हिसाब है कि कभी तो बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि बराबर वहां भुखमरी की सी हालत बनी रहती है । कभी ही कोई ऐसा मौका आता होगा जब वहां कोई हल्ला न मचता हो । हमारी खुशकिस्मती है कि उस इलाके से हमारे मन्त्री महोदय अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जो वहां की समस्या है, उसको भली भांति जानते हैं । वहां पर सिंचाई का कोई इन्तिजाम नहीं हुआ है, कोई छोटी छोटी योजनायें नहीं बनी हैं जिससे सिंचाई का इन्तिजाम हो सके । मेरी अपनी कंस्टिट्युएंसी में जो नेपाल बार्डर पर है, एक ही फसल होती है जो जड़हन की फसल कहलाती है, जिसे ट्रांसप्लांटिंग पैडी कहते हैं । जब पानी नहीं बरसता है तो फसल सूख जाती है और साल साल भर लोगों को तकलीफ और परेशानी में गुजरना पड़ता है । वहां पर लोगों की बहुत बुरी हालत है । डेबरुआ के इलाके में चान्हवा नाम की योजना चार पांच बरस हुए निकाली गई थी लेकिन वह अभी तक भी खटाई में पड़ी हुई है । मालूम हुआ है कि नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐतराज हुआ है और उस योजना की काफी पैरवी नहीं की गई है । नतीजा यह है कि कुछ भी प्रगति नहीं हो पाई है । अब की बार जब सूखा पड़ा तो हालत यह हुई, जहां रुपाई होती थी, ट्रांसप्लांटेशन होता था, वह नहीं हो सका और सारे का सारा इलाका भुखमरी से परेशान है । मैं वहां पर गया हूं, यू० पी० के और भी लोग गए हैं और लोगों ने कहा है कि साहब बारह बरस आजाद हुए हो गए हैं, हमारी एक ही फसल होती है और उसके लिये भी सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया जा सका है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि वहां पर अवश्य ही सिंचाई का इंतिजाम शीघ्र होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इस ओर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देंगे ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर बस्ती, गोरखपुर इत्यादि जिलों की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वह राबती नदी की है । राबती नदी में बाढ़ आने की वजह से जो फसल है, उसको बराबर नुकसान होता रहता है और गांव कट जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को करोड़ों रुपये की हानि प्रतिवर्ष सहन करनी पड़ती है । राबती नदी के बारे में कोई योजना बनाने के लिये और बांध बनाने के लिये बराबर कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे हाउस के एक मेम्बर ने इस सिलसिले में अनशन भी किया था और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने उनको लिखा था कि इस योजना को हम तीसरी योजना में लेंगे । राबती और घाघरा की योजना को इस योजना में अगर ले लिया जाए तो इसका यह लाभ होगा कि बाढ़ से जो परेशानी और बरबादी होती है, वह रुक जाएगी और दूसरा इसका लाभ यह होगा कि सिंचाई के लिये पानी मिलने लग जाएगा, नहरें बन सकती हैं

और जिस इलाके में एक ही फसल होती है उस इलाके का काफी राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शायद इस सिलसिले में जलकुंडी की एक स्कीम आपके पास भेजी है और मैं चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें।

जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हम लोगों को उम्मीद थी कि रिहाण्ड बांध बन जाने के बाद वहां के लोगों को काफी बिजली मिल सकेगी जिससे उनका कुछ धंधा चल सकेगा, उनको कुछ रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे। सन् १९४६ से काम शुरू है लेकिन अब चौदह बरस के इन्तिजार के बाद मालूम हुआ है कि जो बिजली है वह कुछ तो बिड़ला एल्यूमीनियम फैक्ट्री जो है, उसको दे दी गई है और कुछ रेल वालों को दे दी गई है और वहां पर कोई बिजली नहीं मिलेगी। बस्ती, गोंडा इत्यादि को कोई बिजली नहीं मिल सकेगी। तो यह जो जलकुंडी की योजना राबती की है, उससे ३०,००० किलोवाट बिजली भी पैदा की जा सकती है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। अगर इस योजना को हाथ में ले लिया जाए तो बस्ती, गोंडा बहराइच के जिलों को बिजली मिल सलती है और उनका काम चल सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस योजना को हाथ में लिया जाए।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, मेरे जिले में और मेरे पड़ौस के जिले गोरखपुर में काफी काम हुआ है। गांव ऊंचे किये गये हैं जिससे उन लोगों को राहत मिली है। कुछ बांध भी बांधे गये हैं और उन बांधों की वजह से भी कुछ बचाव हुआ है। लेकिन जो बांध बांधे गये हैं, उनमें ऐसा देखने में आया है कि दस मील बांध एक तरफ से बांधा गया और पांच मील एक तरफ से और बीच में एक मील या दो मील, उसको छोड़ दिया गया। इसको छोड़ने का जब कारण मालूम किया गया तो पता चला कि प्लानिंग कमीशन ने जो ग्राण्ट दी थी, उसको कम कर दिया है। इसका नतीजा यह है कि गांव के लोग समझते हैं कि सरकार की स्कीमों पर अजीब तरीके से अमल होता है, दस मील इधर से बांध लाए, पांच मील उधर से और बीच में एक दो मील छोड़ा हुआ है और इसका नतीजा यह हुआ है कि दो तीन बरस से बरसात के मौसम में जो कुछ बंधा है, वह भी खराब हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो एक दो मील तक बांध बांधा नहीं गया है, वहां पर भी बंधवा दिया जाए जिससे जो लाखों रुपया खर्च हुआ है वह बरबाद न हो जाए और किसानों को भी लाभ पहुंच सके।

सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें गूलों का सवाल भी बड़ा भारी सवाल है। गूलें जो हमारे यहां बनी हुई हैं, उनके बारे में हमेशा यह शिकायत रहती है कि पानी नहीं जाता है। अब चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना ली जाने वाली है, उसके दौरान में जो भी अब तक ट्यूबवैल बने हैं, नहरें बनी हैं, उनमें गूलें ऐसी बना दी जाएं कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। ऐसा न हो कि गूलें ऐसी हों कि पानी न छोड़ें और किसानों के खेतों तक पानी न पहुंचे, यहां पर सरकारी कागजों में तो लिखा रहता है कि इतने ट्यूब वैल बन गए हैं, नहरें बन गई हैं लेकिन वहां किसानों को जब पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि फसलें खराब हो जाती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

गूलों की मुरम्मत का सवाल भी पैदा होता है। किसान यह समझते हैं कि जब सरकार हम से दाम लेती है, तो गूलों की मुरम्मत करना सरकार का काम है और सरकारी अहलकार जब वहां जाते हैं तो कहते हैं कि मुरम्मत करना उनका काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी कोई फैसला हो जाना चाहिये। या तो नहर का महकमा इस काम को करे या फिर गांव सभा गूलों की सफाई की जिम्मेवार हो। क्योंकि अगर गूलों की सफाई नहीं होती है तो इसका नतीजा

यह होता है कि जब सूखा पड़ता है, और किसानों को पानी की जरूरत होती है, तो इन गूलों से पानी नहीं जाता है । इस वास्ते इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये और इसका भी कुछ उपाय होना चाहिये ।

वहां पर एक गण्डक की योजना भी निकली थी । अगर गंडक की कुछ नहरें ले ली जाएं तो महाराजगंज की तहसील, नवगढ़ की तहसील, बांसी की तहसील में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और वहां पानी पहुंचाया जा सकता है । मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे ।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय सब हालात से वाकिफ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने रख हैं, उन पर वह ध्यान देंगे इन शब्दों के साथ मैं जो डिमांड्स रखी गई हैं उनकी ताईद करता हूं और आपको, मुझे समय देने के लिय, धन्यवाद देता हूं ।

18 hrs.

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के सम्बन्ध में जो मांगे पेश की गई हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार इस सदन में रखने के बारे में जो मुझे अवसर प्रदान किया गया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की एक खास समस्या, फूड की समस्या है । इस फूड की समस्या को हल करने के लिये अलग से खाद्य मन्त्रालय है लेकिन इस समस्या को हल करने की और मुल्क में खाद्यान्न की उपज बढ़ाने की, ताकि बाहर के मुल्कों से इनका आयात बन्द हो, कुंजी इस मन्त्रालय के हाथ में है । और आपके महकमे की कामयाबी से मुल्क की कामयाबी है आपकी असफलता से मल्क की असफलता है । मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके, नहरों का सवाल आया, और सवाय आये । आजादी के बाद एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और तीसरी आने वाली है । हालांकि यहां सबजक्ट प्लैनिंग का नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप की प्लैनिंग में दोष है, इस प्रकार के दोषों से आप की प्लैनिंग सफर कर रही है, आप की प्लैनिंग अधूरी है । अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री राम शंकर लाल यह कह रहे थे कि नहरों की प्लैनिंग हुई, ट्यूब वैल की प्लैनिंग हुई, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने की प्लैनिंग नहीं हुई । मुझे याद है इंडिपेन्डेंस से पहले उत्तर प्रदेश में शारदा कैनाल बनी शारदा कैनाल की प्लेन पहले बनी, लेकिन पानी पहुंचाने के पहले उन्होंने नहरों का प्राविजन किया, पहले नहरें जायें और नहर से खेत तक गुल बनान का प्राविजन भी उसके साथ किया गया । लेकिन जब से मुल्क अपने हाथ में आया, प्लैनिंग अपने हाथ में आई...

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट में लिखा हुआ है ?

श्री रामजी वर्मा : बड़ी बड़ी प्लैनिंग होने लगीं, तब से नहर बना देने की तो प्लैनिंग है, उसके लिये प्राविजन है, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने की प्लैनिंग के लिये कोई आइट नहीं है, उसके लिये कोई रकम नहीं है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : आप का मंशा रजवाहों से है या छोटी नालियों से ?

श्री रामजी वर्मा : दोनों से है । आप समझते हैं कि खेत तक पानी पहुंचाने के लिये नालियां बनाने का काम किसान खुद कर लेंगे । लेकिन आप की इन रिपोर्टों को पढ़ने से, जो कि पिछले साल की हैं, यह मालूम हुआ कि पानी की सुविधा हो जाने के २० या २५ वर्ष बाद लोगों को पानी लेने का अभ्यास हुआ । इस मुल्क में पानी की जरूरत है, लोग पानी के लिये

परेशान हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है उनसे अपने खेत तक पानी ले जाने की प्रवृत्ति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह चीज श्रमदान के लिये छोड़ दी गई है ।

श्री रामजी वर्मा : आज टैक्सों का सवाल आता है, और चीजों का सवाल आता है, वे लोग जो खेती करते हैं वह बहुत सस्ते ढंग से करते हैं लेकिन जब उन पर टैक्स पर टैक्स लगते है तो इससे वह चिढ़ते हैं, और कोई सुविधा आप की लेना नहीं चाहते । इसलिये मैं कहता हूं कि जो प्लैनिंग आप करें, उसमें आप भले ही रुपया बढ़ा लें, लेकिन आप खेतों तक पानी पहुंचाने का इन्तजाम करें । उसका प्राविजन आप करें तो विरोधी बैंचेज से उसका कोई विरोध नहीं करेगा ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : श्रमदान नहीं चाहते आप ?

श्री रामजी वर्मा : श्रमदान भी करें, उसकी भी योजना बनायें ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : बेगार भी लीजिये ।

श्री रामजी वर्मा : बेगार भी लीजिये, सब कुछ कीजिये और इसको भी भी कायम रखिये । इसलिये मैं पहली बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पानी को खेतों तक पहुंचाने का प्राविजन होना चाहिये, दूसरी चीजों का प्रबन्ध होना चाहिये । आज गवर्नमेंट की मदद से बहुत सी चीजों की इंडस्ट्रीज चल रही हैं । अभी किच्छा में लोगों को मदद दी गई लेकिन कई वर्ष तक उनसे लगान नहीं ली गई । मैं कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को लोगों की पानी लेने की प्रवृत्ति बनाने में २८ वर्ष लग जाते हैं तो चार छः वर्ष तक आप पानी मुफ्त क्यों न दें, और फिर उसके बाद उनसे चार्ज करें ? पानी मुफ्त लेने के बाद जब लोगों को अन्दाजा हो जायेगा कि उनको फायदा हो रहा है तो वह लोग पैसा भी देने लगेंगे । जिस तरह से आज बिजली की मांग इतनी हो गई है, हालांकि वह काफी महंगी है लेकिन फिर भी सब लोगों की मांग उसके लिये हो गई है, सब कहते हैं कि हम को दीजिये, हम को दीजिये, उससे कोई डरता नहीं, जितनी पैदा होती है उससे ज्यादा की मांग है, उसी तरह से पानी के बारे में भी कुछ दिन के बाद होने लगेगा । लेकिन आज तो आप इर्रीगेशन के पोटेन्शल को बढ़ा देते है फिर भी वह पानी सुलभ नहीं होता किसी को । नहरों के जरिये मैं समझता कि पानी फिर नदी में चला जाता होगा या समुद्र में जाता होगा । आपने समुद्र को सींचने के लिये नहरें बनाई है या नदियों को पानी देने के लिये । लोगों की प्रवृत्ति को बनाने के लिये आप को कुछ दिन पानी के रेट में कमी करनी होगी या बिल्कुल मुफ्त देना होगा, कुछ दिन तक यह रिस्क ली जायेगी तभी जल्दी से मुल्क को नहरों से पानी लेने का अभ्यास हो सकेगा । उसके बाद आप चार्ज कर सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं । यह मेरा जो सजेशन है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और खेतों तक रजवाह बनवाने का प्रबन्ध करेंगे ।

इसके बाद मैं ट्यूब वैल्स के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि ट्यूब वैल्स छोटी सिचाई योजना में आते हैं, बड़ी में नही आते । लेकिन इस मुल्क में कुछ लोगों को गुमराह करने के लिये कह यह दिया जाता है कि जो बैकवर्ड एरियाज है उनकी सिचाई के लिये यह सुलभ साधन हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसमें ट्यूब वैल बनाये गये हैं जैसा कि श्री राम शंकर लाल जी ने बतलाया, लेकिन मैं आप से कहूं कि आप के पास हिसाब होगा, जो ट्यूब वैल्स का कमाण्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट में, उसके पानी से सब ट्यूब वैल्स मिल कर भी उतनी सिचाई नहीं कर सके हैं जितनी कि आम तौर से हो जाती है । वहां पर गूल नहीं हैं खेतों तक पानी लाने के लिये, उसके बारे में लोगों की प्रवृत्ति

[श्री रामजी वर्मा]

नहीं पानी लेकिन टैक्स जो लगाये जाते हैं वह बहुत ज्यादा हैं । इस समय जो नये आपरेटर्स लगाये गये हैं देहातों में वे पटवारी और लेखपाल से भी ज्यादा जबर्दस्त हो गये हैं, किसी के पानी किसी के खेत में लगा देते हैं । इस तरह की आफिशलडम के कारण दूसरे आदमी का पानी दूसरे खेत में लगा दिया जाता है । इससे लोगों को बचाने के लिये भी आप को कुछ करना होगा ।

श्री त्यागी : यह राज्य सरकारों का काम है ।

श्री रामजी वर्मा : भले ही यह राज्य सरकारों का काम हो, यों तो हमारे सरदार इकबाल सिंह जी ने कहा था कि इन सिंचाई योजनाओं को आप अपने हाथ में लीजिये, लेकिन जब तक आप उन को नहीं ले सकेंगे, तब तक छोटे छोटे कुओं के अलावा किसी और तरह की सिंचाई सफल नहीं हो सकती । आप इन चीजों को अपने हाथ में लीजिये और इन सब चीजों को देखिये । मैं आप से कहता हूं कि सारा सिंचाई का पैसा जो है वह ट्यूब वैल्स में, नहरें खोदने में, कंट्रैक्ट्स को देने में और समुद्र को सींचने में जाता है । कुछ से तो आप समुद्र को सींचते हैं और कुछ से बड़े बड़े ठेकेदारों की पाकेट सींचते हैं किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो रही है । पर शब्द भले ही कटु मालूम हों, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिये, योजना के अनुसार खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये, और अगर उसम कोई करप्शन की बात आती हैं तो उनको दूर करने के लिये, आप कदम उठाइये । आप यह कह कर पल्ला मत छुटाइये कि यह स्टेट का विषय है । अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि किसान पानी लेंगे । यदि आप कुछ दिन तक मुफ्त पानी देने की व्यवस्था करें, तो उसके बाद लोगों की प्रवृत्ति बन जायेगी और जो आप का इरिगेशन पोटेंशल है उसके लिये यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि लोग उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं । उसके बाद आप का पानी बेकार समुद्र में नहीं जायेगा ।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जिस तरह से बहुत से मामले खटाई में पड़ गये हैं, काश्मीर का मामला है, गोवा का मामला है, और मामले हैं, उसी तरह से जो हमारी प्रगति की कुंजी है उसका भी एक हिस्सा इन्डो–पाक कैनाल वाटर डिस्प्यूट के नाम से उलझा पड़ा है । उसका एक अध्याय बन गया है । यह आप की भी बदकिस्मती है । सरदार इकबाल सिंह ने कहा कि कुछ दिन से यह मामला भी खटाई में पड़ गया है । आप के पूर्व मंत्री ने घोषणा कर दी थी कि सन् १९६२ के बाद हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे । अच्छा होता अगर यह मामला उसके पहले तय हो जाता, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि यह मामला कहां है और उसका क्या हो रहा है । हम चीन के मामले को तो कुछ समझते भी हैं, काश्मीर के मामले को भी कुछ समझते हैं, लेकिन यह जो वाटर डिस्प्यूट का मामला है वह मेरी समझ में नहीं आता है । उस की बैठकें कभी वाशिंगटन में होती हैं, कभी पेरिस में होती हैं और कभी लन्दन में होती हैं, और पता नहीं उसके बारे में क्या क्या होता है । कुछ पता ही नहीं चलता है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में क्या हो रहा है । अब यह करोड़ों आदमियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है और अगर शीघ्र ही यह नहरी पानी विवाद हल किया जाय तो अच्छा है । अभी राष्ट्रपति श्री नासिर ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं इस बारे में दोनों पक्षों में समझौता कराने के वास्ते तैयार हूं और उस के बाद पाकिस्तान के जनरल अय्यूब खां ने भी फरमाया कि हम भी समझौता करने को तैयार हैं । अब अगर दोनों साहब समझौता कराने और करने के वास्ते

तैयार है तो क्या भारत सरकार ही उसके लिये तैयार नहीं है ? इसमें तो यह ध्वनि निकल रही है मानों सब लोग तो तैयार है केवल भारत सरकार उसके लिये तैयार नहीं है । मैं समझता हू कि आप समझौता करने के वास्ते उनकी अपेक्षा अधिक उत्सुक व तैयार होंगे लेकिन मैं चाहता हू कि मंत्री महोदय इस ओर प्रकाश डाले कि आखिर बात क्या है कि सब अपने को तैयार बतलाते हैं तो फिर वह मामला आखिर तय क्यों नहीं होता है ? ऐसा क्यों है ? मैं बतलाना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे श्री खुशवक्त राय एक काम रोको प्रस्ताव यहां सदन में लाये थे लेकिन जैसा कि अक्सर देखने में आता है माननीय अध्यक्ष ने उस काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसकी भी वही हालत हुई जैसी कि अन्य काम रोको प्रस्तावों की हुआ करती है । इस कारण उस अवसर पर इसके बारे में बहस उठाने का तो मौका नहीं आया लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में अवश्य बतलायेंगे कि आखिर इसमें राज क्या है और यह मसला कब तक हल हो जाने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रामजी वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल से आता हूं, और मुझे तो कुछ अधिक समय मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करें और दो की जगह तीन मिनट का समय ले लें ।

श्री रामजी वर्मा : मैं बिजली के सिलसिले में भी कुछ बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं । जहां बिजली उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये है वहां सिंचाई और खेती के काम के लिये भी बिजली की काफी जरूरत होती है लेकिन जो आपकी रिपोर्ट छपी है तो उसमें घरेलू कामों के लिये आप बिजली १६–२५ नये पैसे के हिसाब से सप्लाई करते हैं, उद्योग धंधों के लिये ४–६० नये पैसे, कृषि के लिये ६–७८ नये पैसे और अन्य कामों के लिये ७–१२ नये पैसे की यूनिट की दर से बिजली सप्लाई करते हैं. . . .

श्री हाथी : यह कहां का रेट है ?

श्री खुशवक्त राय : यह सन् ५७–५८ की सेंट्रल वाटर एंड कमिशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है ।

श्री राम जी वर्मा : मेरा कहना यह है कि यदि आप कृषि की उन्नति करना चाहते हैं तो आपको बिजली के वर्तमान रेट को सस्ता करना चाहिये । आप बिड़ला, टाटा और अन्य बड़े बड़े उद्योगपतियों को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करते हैं और मंत्री जी खुद इसको बतलायेंगे कि रिहेन्द डैम की बिजली बिड़ला की एलमूनियम फैक्टरी को कोस्ट प्राइस से भी कम पर दी गई है । अब यदि इन बड़े बड़े व्यवसाइयों को जब बिजली सस्ती दर पर दी जा सकती है तो फिर किसानों से बिजली का अधिक रेट क्यों लिया जाता है ? क्या इस देश के किसानों के पास उनकी अपेक्षा अधिक पैसा हैं जो आप उनसे बिजली का अधिक चार्ज करते हैं ? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस चीज को साफ कर देंगे कि आखिर इन छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों को और कृषि वालों को बिजली महंगी दर पर क्यों सप्लाई की जाती है ? उनको सस्ते रेट पर बिजली क्यों नहीं सप्लाई की जाती ?

अब देश में विभिन्न प्रांतों में बिजली का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वह इस प्रकार है :—

बंगाल	६५–६८
मैसूर	२३–४२
पंजाब	२०–५
बम्बई	५५–६४
केरल	२३–२४
उत्तर प्रदेश	१०–९६
मद्रास	३१–४४
बिहार	१०–८

[श्री पामजी वर्मा]

इससे आपको मालूम पड़ जायेगा कि जो पिछड़े हुये इलाके उत्तरप्रदेश और बिहार के हैं तो इनका कंजम्पशन पर कैप्टा १०-९६ पड़ता है और इसके रहते यह इलाके क्या तरक्की कर सकते हैं ? अब इसके लिये यह कहना कि उधर बिजली होती नहीं है ठीक नहीं होगा क्योंकि जो रिहान्द डैम बना था तो उसकी बिजली आपने बड़े बड़े व्यवसाय वालों को दे दी और सस्ती दर पर दे दी । अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नदियों में पानी बहुत है और जिसका कि जिक्र श्री राम शंकर लाल ने किया है । राप्ती के साथ घाघरा को भी जोड़ लिया जाय और यदि आप इन प्रोजेक्टों को लें तो आपको केवल सिंचाई के लिये पानी ही ज्यादा नहीं मिल सकता है बल्कि बिजली भी ज्यादा सुलभ हो सकती है और मैं समझता हूं कि इनसे इतनी अधिक बिजली पैदा होगी कि शायद सारे देश को हम पावर सप्लाई कर सकेंगे । अब इसके लिये जब कि भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हुआ था तब से राप्ती और घाघरा के सिलसिले में जांच पड़ताल हो रही है और उसकी योजनायें और सर्वे भी काफी दिनों पहले से हो चुका है और मैं चाहूंगा कि उस प्रोजेक्ट के बनने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इस पर मंत्री महोदय सदन में कुछ प्रकाश डालेंगे और इसको थर्ड फाइव इयर प्लान में लेने की कहां तक गुंजाइश है ?

इसी तरह गंडक प्रोजेक्ट की बात है । अब नैपाल की सरकार ने इसको कबूल कर लिया है तो फिर इसके बनने में देरी क्यों हो रही है ? इसके अलावा उससे जो पश्चिम में गोरखपुर और बस्ती की तरफ नहर निकाली गई है तो उसका पानी आधे ही जिलों तक दिया गया है और उसको अगर रोहिन नदी के पार भी ले जाया जा सके तो मैं समझता हूं कि उससे हम बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों को अधिक परिमाण में सिंचाई की सुविधायें दे सकेंगे और बिजली भी सस्ते रेट पर दे सकने में समर्थ हो सकेंगे । इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

बाढ़ के सिलसिले में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । यह सवाल सबसे पहले उत्तरप्रदेश की ही बाढ़ों से उठा और माननीय खाद्य मंत्री और योजना मंत्री ने सरकार की तरफ से ऐलान किया कि बाढ़ की समस्या को हम वार फुटिंग पर लेंगे लेकिन तब से मैं देख रहा हूं कि यह बाढ़ों की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है और बाढ़ों के हमलों में भी वृद्धि ही होती जा रही है और अब यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल न रह कर भारत के कोने कोने का सवाल बन गया है । अब यह वार फुटिंग पर जितने काम हम कर रहे हैं उनमें हम कहां तक सफल हो पा रहे है ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें भी यह ठेकेदार और दूसरे स्वार्थी तत्व आने लगे हैं पैसा तो लगाया जाता है लेकिन काम ढंग से नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये गम्भीरतापूर्वक सोच समझ कर सक्रिय कदम उठायें । उत्तर प्रदेश की राप्ती और घाघरा नदियों का यदि कंट्रोल हो जाता है तो जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो सकेगी, वहां बिजली भी अधिक पैदा होगी और यह जो बाढ़ों के कारण हर हाल फसलें बर्बाद हो जाया करती हैं वे भी बर्बाद होने से बच जायेंगी । आये साल इन नदियों में बाढ़ आने से जो बर्बादी होती है उससे आप लोगों की रक्षा कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि जिस चीज को आपने वार फुटिंग पर लिया हुआ है उसके बारे में इतनी देरी होना आश्चर्यजनक है और आपको इस बारे में सक्रिय कदम उठाने चाहियें ताकि अब और अधिक देरी इनके पूरा होने में न लगे । मैं आशा करता हूं कि मैंने जो चन्द एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे और केवल इस वजह से उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे कि यह

विरोधी दल की तरफ से दिये गये हैं । मंत्री महोदय को ऐसे सब सुझावों को चाहें वे विरोधी दल की तरफ से हों अथवा सरकारी पक्ष से हों ऐसे सुझाव जो कि जनसाधारण और देश के हित और उन्नति में सहायक हों उनको सरकार को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिये । इस देश की करीब ७५ प्रतिशत आबादी का मुख्य धंधा कृषि है लेकिन उसके प्रति जो सरकार का उपेक्षा भाव है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । आपको कृषि के धंधे में लगे लोगों को पानी और पावर की सुविधा देनी चाहिये और यह दोनों चीजें उसको सस्ते रेट पर मिलनी चाहियें ताकि उसको खेती करके देश की उपज बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले और ऐसा करके आप देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे जो कि आज हमारी सब से बड़ी आवश्यकता है । आप यदि ऐसा करेंगे तो आप न सिर्फ अपने देश की उन्नति करेंगे बल्कि दुनिया की प्रगति में भी आप सहायक होंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सबके बधाई के अवश्य पात्र बनेंगे ।

Mr. Speaker: I propose in the first round to give opportunity to each State. I am prepared to give an opportunity now to Bihar. Dr. Ram Subhag Singh and Pandit D. N. Tiwari may decide between themselves.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): The size of the State may also be taken into consideration.

Mr. Speaker: I have already called three hon. Members from Uttar Pradesh.

Shri Tyagi: A State which has been neglected must be given preference.

Mr. Speaker: Uttar Pradesh (*Laughter*).

Shri Rameshwar Rao (Mahbubnagar): A State which is newly-born should also be given preference.

Mr. Speaker: I will call Andhra next and then Mysore.

Shri Ram Krishan Gupta (Mahendragarh): The Hindi-speaking area of Punjab may also be given an opportunity.

Shri Maniyangadan (Kottayam) *rose*—

Shri Basappa (Tiptur) *rose*—

Mr. Speaker: I am going to give an opoprtunity to one Member at least from each State. Pandit D. N. Tiwari.

Pandit D. N. Tiwari (Kesaria): Mr. Speaker, Sir, I wish to congratulate this Ministry for the good work done by it during the first and second Five Year Plans. The Ministry has done a very good work and although they were charged with the duty of discharging a very stupendous work, their achievements in both the first and the second Five Year Plans have been remarkable. It is true that the success of our plans depends mostly on this Ministry. Just as the food problem is at the core of the success of the Plan, this Ministry is at the core for the success of agriculture, and it has got to discharge a very onerous duty. It is for this Ministry to see that through the execution in time of all the plans for irrigation the success of agriculture is assured and thereby the success of the Plan is assured. Otherwise, if agriculture fails, the Plan will fail. There is no dearth of water in this country. We have got about 13,056 million acre-feet of water. In 1951, only 5·6 per cent. *i.e.*, 6 million acre-feet, had been tackled. In the first and second Plan, the figure is 154 million acre-feet. That is also not a very laudable target. If some efforts are made to tackle more, the problem of food and agriculture will be solved.

I wish to draw the attention of the Ministry about the utilisation of the water resources. Some friends have said that water potential has been

[Pandit D. N. Tiwari]

created, but due to some fault in the planning and also in the execution, water is not fully utilised; they go waste. I am not of the opinion that free water should be given to the cultivators. The cultivators like to pay, but the facilities should be provided to them to irrigate their land. This Ministry of Irrigation should be run on a commercial basis. I do not think more irrigation facilities can be created if loss is incurred. No undertaking can last for long if there is loss. This should be done on a commercial basis, so that there may not be any loss and the money granted to this Ministry may be gainfully employed for further progress of irrigation.

Having said this, I wish to draw the attention of the Minister to the organisational pattern of this Ministry. At the present moment, there are three kinds of works: major, medium and minor. Major works are under this Ministry and minor works are under the Agriculture Ministry. This sort of dividing irrigation under two Ministries hampers the work and also delays execution. We have seen that minor irrigation works yield quick results and are less expensive. More attention should be given to minor irrigation works, but due to this division of functions between the Ministries of Irrigation and Power and Agriculture, not much work is done. Therefore, the benefit that should have accrued to the agriculturists does not accrue to them.

There is another difficulty about the organisation which becomes responsible for carrying out major irrigation works. At present there are three sorts of organisations in the country. One is the corporation, another is the control board and the third is departmental. I think if one set of organisation is made in charge of all the irrigation works in the country, that would have been better and would have served the purpose; the execution of the work would also have been done in a better way. Government should think and try to bring all the irrigation works under one pattern of organisation and not divide it into three patterns. I think the works done by the department departmentally are not very encouraging. There is red-tapism and also other hindrances in departmental work.

In addition, there is another defect. They become very independent and immune to public criticism. In my opinion, a control board should be set up for all major irrigation works so that the work of all construction works are expedited and they are economical.

Now I come to the problem of the utilisation of idle machinery. In most of our major irrigation works which have been completed there is machinery lyng idle which can be put to better use in other projects. One committee was also set up by the Ministry called Machine Utilisation Enquiry Committee or some such thing. Some benefit has accrued from their suggestions. But I think there is still scope for improvement and better ulilisation of the machinery. We must see to it that there is better utilisation of the machinery which are lying idle in most of the major irrigation work sites.

Now I come to my State. There are three major irrigation works in hand in my State and they are the DVC, Kosi and the much neglected Gandak though now some attention is being paid to that also. It is accepted on all hands that Gandak is the cheapest and the best revenue yielding project. But that was taken last and still not much attention is paid to that. Even though some allotment has been made to this project this year, I am sorry to say that the work has not begun yet. Also, the allotment made is so inadequate that actually no work can be done. I would appeal to the Minister that after the finalisation of the agreement with the Nepal Government no time should lost in proceeding with the work and it should be execut-

ed at an early date, because this is the project which can irrigate more land in Bihar than any other project. DVC is useless on the score of irrigation. Although 20,000 acres were proposed to be irrigated by DVC, even up to now not a single acre of land has been irrigated and no arrangement has been made yet for irrigation from the DVC in Bihar. I know that electricity is being produced. Of course, some portion has also come to Bihar. But Bengal gets the most of them.

There is no special benefit from DVC to Bihar. If irrigation has been done from DVC Bihar would have reaped some benefit. About Kosi propect we have found that it is beneficial in so far as it has prevented the recurrence of floods in that area. Some irrigation potential is also being created by that, but the western side of Kosi in Darbhanga has not been taken up for irrigation, although no extra expenditure is required and no new dam is required with very little cost some three million to four million acres of land could be irrigated. I do not know why the Ministry has not taken up this work. I would appeal to the Minister to take up this work also so that lands in Darbhanga where water is needed most are made cultivable.

About the execution of projects I would point out that Kosi has shown the way. We have found that if the works are done on public co-operation basis, not through contractors but through such organisations as the Bharat Sevak Samaj, the cost becomes less.

In Kosi we have found that the Bharat Sewak Samaj has been able to execute, I think more than 35 per cent of the work on bunds etc. There the cost has been reduced by 30 to 35 per cent. If the Bharat Sewak Samaj had not been there the cost would have risen much more, even more than the estimated cost. But now we find that the work there has been done at less than the estimated cost by as low as 25 to 30 per cent. So this experience of Kosi should be taken note of and should be utilised in other projects.

Gandak project is going to be taken up soon. I would appeal the hon. Minister to work on this pattern there so that the cost may be less and the work through public co-operation may be given a fillip.

About minor irrigation works in Bihar I would like to mention one thing. Under minor irrigation wells have been excavated but they are not able to irrigate even one acre of land. The defect lies there with the wells. They have no water. Some boring is necessary so that the wells may be useful for irrigation. When the cultivators or the well owners who have been helping in digging the wells go for some machine they are told that no machine is available. Thus all the expenses so far incurred on that well becomes useless as no irrigation is done. There are thousands of wells in Bihar which were to be utilised for irrigation purposes but they have become dry and are not being so utilised. Attention should be given to that aspect of the matter and machinery and other things should be sent there so that the cultivators may utilise the wells for irrigation purposes.

Shri Rami Reddy (Cuddapah): Mr. Speaker, Sir, at the outset I would like to congratulate the Ministry for the splendid work that it has done in respect of at least two matters, that is, in respect of economies effected in some of the river valley projects and utilisation of water pontential. In three projects alone the Ministry has been able to effect economies to the extent of Rs. 9 crores and it is really a commendable thing. Then in regard to the utilisation of the water potential created during the First and Second Plan periods which in the year 1957 was only 62 per cent, last year they have been able to achieve utilisation of 82 per cent. This also is really commendable. 82 per cent. of the water potential has been untilised. From

[Shri Rami Reddy]

64 per cent. in two years it has been raised to 82 per cent. This also is really commendable. Then in regard to the untilisation of surplus machinery also they have been doing great efforts and I have no doubt that they will be able to utilise fully all the surplus machinery that is available at some of the major river valley projects.

Having said this I would like to say something about power. The extension of electricity is basic to the development of the country. It constitutes the foundation of all future progress, both in the industrial and rural fields. The economic prosperity of a State largely depends upon the rapid progress of the rural areas. Among the many measures undertaken to develop and improve the standard of living in the country supply of electricity plays a very vital role. Power improves the earning capacity of the villagers, removes unemployment and under-employment and removes the drudgery of rural life. Therefore I submit that great emphasis should be laid on power development in the country.

Sir, coming to my State, the *per capita* consumption of electricity is only 7 units at the beginning of the Second Five Year Plan. The *per capita* consumption of electricity is considered as an index of the economic development of any region or any country. From this point of view the Andhra Pradesh State has been very backward both industrially as also otherwise.

Andhra Pradesh State is rich in mineral wealth; it commands abundant water wealth; it is the principal supplier of coal in South India; it accounts for all the production of barytes in the country; it accuonts for half the production of asbestos in the country; it accounts for 11 per cent. of the total production of Manganese and Mica and it has also considerable deposits of iron ore. It has also a major port Vizagapatnam and there are some other minor ports also. It has also good canal system.

Sir, in spite of all these basic necessities available for the development of industries, the industrial development has been very poor in my State. Why is it? It is because the most basic necessity for industrial development, namely, the power has been very much lacking in my State. In spite of the great efforts made by the State Government, the Centre has not been coming forward to help the State in giving them more allocations for power.

In this connection, I would like to mention that in respect of all the other States the plan provision for power in the Second Plan was greater than the plan provision made in the First Plan. The increase in the plan provision ranged from 20 to 80 per cent in respect of other States. But in respect of the Andhra Pradesh State, the plan provision in the Second Plan was lower than the plan provision made in the First Plan. I have got some figures which I would like to read. In respect of the Andhra region of the Andhra Pradesh the provision in the First Plan was Rs. 25.65 crores whereas in the Second Plan it was Rs. 21·66 crores which accounts for 16 per cent lower than the provision made in the First P.an. Of course, subsequently this plan provision was raised. On account of the several representations made by the Andhra Pradesh Government the plan provision was raised from Rs. 21.66 crores to Rs. 24 crores. This was as far as the Andhra region of the Andhra Pradesh State was concerned. Even though the plan provision was raised by Rs. 3 crores, it was still less than the provision made in the First Plan. This is a very regrettable feature.

Apart from this, I would like to mention that some of the projects which were included in the First Plan and which were continuing schemes as far as the Second Plan was con-

cerned, were also not completed on account of the requirements of foreign exchange not being allotted to Andhra Pradesh.

As regards the Tungabhadra Hydro-Electric scheme, this scheme was sanctioned in the First Plan by the composite Madras State and some of the units were also completed in the Second Plan. It is a continuing scheme. When the foreign exchange position became difficult, some of the power projects were included in the core of the Plan. The priority was given for the continuing schemes to be included in the core of the Plan. Now, Sir, this Tungabhadra Hydro-Electric Scheme was a continuing scheme because it was taken up in the First Plan. This continuing scheme which ought to have been given priority, which ought to have been included in the core of the Plan was not included in the core of the Plan. Therefore, the 5th unit of the Tungabhadra Hydro-Electric scheme has not yet been completed. I would, therefore, request the Ministry to see that the foreign exchange content required for completing this 5th unit of the Tungabhadra Hydro-Electric scheme is sanctioned immediately and the scheme is completed. This Tungabhadra Hydro-Electric Scheme—Second Stage also is essentially a continuing scheme, because it was included in the Second Plan itself, but, for the same reason, the completion of this project also is held up. Here, the power-house buildings are completed, other civil works also are completed, the expenditure has been incurred, but, for want of generators, the scheme has been held up. This scheme serves the needs of very backward areas in the Andhra State, such as the Rayalaseema area. On account of the non-completion of the Tungabhadra hydro-electric scheme, the power supply in that area has been very poor; it has been retarded and there has been severe rationing of power supply in the State. Therefore, I would request the Ministry to accord priority for this Tungabhadra hydro-electric scheme.

Coming to Plan allocations in the Third Plan, I would request that greater allocations should be made for the power sector in the Third Plan. As I said earlier, the provision for power development in the Second Plan has been lower than that in the First Plan, and the *per capita* consumption in Andhra Pradesh at the beginning of the Plan is only 7 units as compared to 18 expected at the end of the Plan.....

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): 25 is the all-India average.

Shri Rami Reddy: It is only 7 units as compared to the all-India average of 25 units. At the end of the Second Plan, the *per capita* consumption in Andhra Pradesh is expected to be about 18 units as compared with the expected all-India average of 50 units for the whole country. That means that Andhra Pradesh would be lagging 32 units behind the all-India average.

From the statistics published by the Central Water Power Commission, I find that in the second year of the Plan, that is, in 1957-58, in the industrial sector, about 4·46 units were being utilised in Andhra Pradesh State by industries, whereas the all-India average was 17·84 units. From this, it can be known how backward Andhra Pradesh is in regard to power utilisation.

The load survey conducted by the Central Water Power Commission has disclosed that there would be a severe shortage of power during the Third and Fourth Plan periods. According to the survey conducted, the power that ought to be generated in the Third Plan to meet the requirements of the Andhra Pradesh State in the Third Plan would be about 400 M.W. and in the Fourth Plan, it would be 600 M.W. The generating capacity by 1960-61, including the power that would be generated by the Tungabhadra hydro-electric scheme would be about 205 M.W. That means, the additional generating capacity to be achieved during the

[Shri Rami Reddy]

Third Plan under new schemes would be about 250 M.W. Therefore, a higher allocation for the power sector is absolutely necessary.

From the figures available in respect of the number of villages that are electrified, we find that out of about 26,500 villages that are there in Andhra, only about 1082 villages, that is, 4 per cent of the number of villages in Andhra alone are electrified so far. Even from this point of view, the necessity for a higher allocation for the power sector is evident.

In this connection, I would like to mention a word about the Srisailam project which has been sent up by the State Government for consideration by the Central Water Power Commission and inclusion in the Third Plan. The Srisailam project would keep intact the benefits under the Siddeswaran project. In fact, it makes possible the entire power avilable at Srisailam and Siddeswaran to be generated at one place, that is, at Srisailam alone, thus avoiding the construction of two dams with appertunant works of power houses and other connecting transmission lines etc. This project is centrally located and it is almost equidistant from the Telengana area, the Rayalaseema area and from the Circar districts. Therefore, it will be easier for the distribution system to operate. It is one of the most economical projects. It is stated that it would cost only about Rs. 600 per kw. of installed capacity whereas elsewhere in the country power projects are costing from Rs. 1,000 to Rs. 2,000 per kw. of installed capacity. So it is one of the cheapest and highly remunerative projects, and I have no doubt that the Central Government would include it in the Third Plan.

It is here that I want to mention something about my constituency, that is, Cuddapah district. As I said, the Srisailam project would keep intact the irrigation facilities under the Siddeswaran project. The Krishna Pennar East Canal and the Krishna Pennar West Cana are expected to irrigate about 3 lakh acres. I quote from a report of a statement made by the Minister for Public Works in the Assembly as reported in the Hindu. He said:

> "The Special Chief Engineer (Irrigation) is of the view that the irrigation benefits will be the same as in the case of the Siddeswaran project and it will be possible to irrigate a direct ayacut of 3,12,572 acres under the Krishna Pennar East and West Canals, besides giving a supply of 1,000 cusecs limited to 45 TMC to the Somasila project...."

In this connection, I would like to mention that the Krishna Pennar project was originally investigated by the Madras Government to give benefit mainly to the backward districts of Kurnool, Cuddapah and Chittur and give water supply to Nellore district—which is also backward— to Madras City and so on. But the main object in investigating the possibility of the Krishna Pennar project was to serve the irrigation needs of the backward districts of Cuddapah, Chittur and other districts.

In this connection, I may say that it was also expected that the Krishna Pennar West Canal would feed the Mylavaram reservoir of New Gandikota Project on the Pennar with a discharge of about 1,800 cusecs through the Krishna Pennar West Canal. This reservoir will irrigate 1·5 lakh acres in Cuddapah district.

Though the Chief Engineer of Andhra Pradesh has stated that the irrigation benefits that would be available under the Siddeswaram project would be the same, there is a lurking suspicion in the minds of the people of the Cuddapah district that the ayacut may not be the same as was contemplated to be irrigated under

the Siddeswaram project. The extent of the ayacut may be equal, but the ayacut may not be identical. As I said, the Krishna Pennar West Canal was expected to feed the Mylavaram reservoir at Gandikota and that reservoir is expected to irrigate about 1¼ lakh acres. If the suspicion proves true, the Cuddapah district stands to lose to a very great extent. There are no other irrigation facilities available for the Cuddapah district. Therefore, I would request the Ministry and the Central Water and Power Commission, when it comes up for examination, to see that the irrigation benefits that would have been available under the Krishna Pennar project are made available under the Gandikota project to the Cuddapah district.

In this connection I would like to mention only just two words in respect of the Tungabhadra High Level Canal scheme. I have raised this question of the Tungabhadra High Level Canal about half a dozen times in this House; and I have mentioned on several occasions that the second stage of that scheme should also be sanctioned even now though the expenditure might be spread over a number of years. We are not particular that the second stage also should be executed immediately, simultaneously with the first stage of the project. It may be taken up after the completion of the first stage. We do not mind that.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Rami Reddy: Just one or two minutes more, Sir.

Mr. Speaker: I have allowed him sufficient time. (*Interruptions*).

Shri Rami Reddy:. Pochampad, I leave it to Shri Rameshwar Rao. I request this Ministry to sanction the second stage of the Tungabhadra High Level Canal scheme even now though the expenditure on the scheme, the execution of the scheme may be spread over any number of years.

As I have said here repeatedly, under the Mackenzie scheme, in 1904 it was envisaged that the Pulivendala taluk was expected to be irrigated to the extent of 1½ lakh acres. Under the 1954 scheme, 55,000 acres were expected to be irrigated in the Pulivendala taluk and under the Gandikota reservoir about 150,000 acres were expected to be irrigated. But under the revised programme, Pulivendala scheme is completely eliminated and under the Gandikota reservoir, the ayacut is reduced from 1½ lakh acres to 70,000 acres. Therefore, the net result is that Pulivendala taluk is completely eliminated and half of the ayacut of Gandikota is reduced.

By the scheme being phased in two stages and only the first stage being sanctioned, Cuddapah district, which would be benefited only under the second stage, is completely eliminated. It is absolute injustice to Cuddapah district. Therefore, I appeal to the hon. Minister to see that the second stage also is sanctioned straightway now though the expenditure may be spread over a number of years.

Shri T. B. Vittal Rao: What about congratulations? (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: Shri Basappa.

Shri Basappa (Tiptur): Mr. Speaker Sir, I am glad I have been given this chance to speak on the Demands of this Ministry even though at the end of the day. (*Interruptions*). The importance of this Ministry is seen in writing the potentialities of power and irrigation in this country. The industrial and agricultural development of this country naturally depend upon the irrigation and power potential. Therefore, this Ministry assumes very great importance. From that point of view, if we study the various plans that have been, from time to time, framed, the First Five Year Plan and the Second Five Year Plan, have laid emphasis on irrigation and power.

I notice that in the Second Plan period power production has received an outlay of nearly Rs. 427 crores and the irrigation pool is about Rs. 381

[Shri Basappa]

crores. That means an additional 3·5 million kws. of power to be generated and about 15 million acres of land to be irrigated. Even though all this is there, I find there is so much shortage in the country. Wherever we go, we hear of shortage of power. Our hon. friend was also saying that nearly 60 to 70 lakhs acres of cultivable land is but irrigation is not there.

19 hrs.

We find that only one-third of the cultivable land is brought under irrigation by this irrigation potential we are creating. With regard to power, my hon. friend has already pointed out that our *per capita* consumption is 50 kws. compared to 1,573 kws. in U.K. and 3,695 kws. in U.S.A. From this we can see to what extent we are short in power. So, the irrigation and power potential should be taken into consideration in the future development. More foreign exchange should be granted to these things. My hon. friends point out: what about the utilisation of the existing water potential? The power generated is used up but with regard to the irrigation potential, there is a controversy. The Ministry should give us a correct picture of the magnitude of the unutilised power potential in the country. The soils in the Northern India are very loose and we are told that about 40 per cent of the water is absorbed by the canals themselves. The community development movement can help here and the village people can take up this work of lining the canals properly so that there will be less wastage of water. As Dr. Ram Subhag Singh has pointed out, the water levy and the betterment levy and all these things are coming in the way of greater utilisation. Our Government has given suggestions to the State Government to see that reasonable rates are fixed in this matter.

Mr. Speaker: The hon. Member may continue tomorrow. Members may now move their cut motions to various Demands for Grants subject to their being otherwise admissible.

Failure to take effective drainage Schemes for water-logging areas

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (575)

Failure to utilise properly the irrigation potential created by Irrigation Development Projects

Shri Ignace Beck: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1225)

Failure to realise irrigation targets in the Second Five Year Plan

Shri Ignace Beck: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1736)

Revision of policy regarding irrigation rates

Shri Ignace Beck: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1737)

Need for evolving policy regarding operation of multipurpose river valley projects

Shri Ignace Beck: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1738)

Payment of statutory compensation to workers of Hirakud Dam whose services were terminated on the 1st April, 1960.

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and

Power' be reduced by Rs. 100." (1796)

Failure to pay construction allowance to workcharged staff of Hirakud

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1797)

Need to give same scales of pay and conditions of services to the Hirakud workers taken over by Orissa Government.

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1798)

Common grid for power supply for South Zone

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1799)

Need for providing work to surplus construction workers of Panchet Dam of the D.V.C.

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1800)

Failure to tap and utilise the power available in Kerala State

Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1801)

Need for completing the investigation of Idikky Project expeditiously for inclusion in the Third Five Year Plan

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1802)

Necessity to create a Central Pool of technical personnel to give them continuous employment.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1803)

Need to provide top priority in the allotment of foreign exchange for the Hydro-electric projects of Kerala.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1804)

Need to take final decision regarding the Master Plan submitted by the Kerala Government regarding the utilization of irrigation and power potential of Kerala State.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1805)

Need to reduce the consumption price of electricity in accordance with the low cost of production obtained in Kerala State.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1806)

Need to include the Kallada flood control scheme of Quilon District of Kerala State in the Third Five Year Plan.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1807)

Need to give more financial assistance to complete rural electrification schemes in Kerala State.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1808)

Need to provide funds for anti-sea-erosion works in Kerala State.

Shri Warior: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1809)

Need for extending the Western Canal from Gandak Barrage to be constructed at Bhanisa Lotan upto Basti District by constructing a siphon across River Rohini.

Shri S. L. Saksena: I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (1810)

Flood control problem in Orissa

Shri Supakar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Multipurpose River Schemes' be reduced by Rs. 100." (1)

Slow progress in the investigation on Tikkerpara and Naraj Dams Projects.

Shri Supakar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Multipurpose River Schemes' be reduced by Rs. 100." (2)

Problem of retrenchment of employees from the Hirakud Dam Project

Shri Supakar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Multipurpose River Schemes' be reduced by Rs. 100." (3)

Need to include a multi-purpose river valley scheme to control the Ghaghra and the Rapti in the Third Five Year Plan.

Shri S. L. Saksena: I beg to move:

"That the demand under the head 'Multipurpose River Schemes' be reduced by Rs. 100." (360)

Rural electrification.

Shri Supakar: I beg to move:

"That the demand under the head 'Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power' be reduced by Rs. 100." (6)

Mr. Speaker: These cut motions are now before the House.

19.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the April 13, 1960/Chaitra 24, 1882 (Saka).